जून 2024
खंड - XL | अंक - II

एक्ज़िमिअस:
निर्यात लाभ

इस अंक में

- पूर्वी अफ्रीका में भारत के लिए आर्थिक अवसर
- तेलंगाना से निर्यात को बढ़ाना: ट्रेंड और नातिगत परिदृश्य
- भारत–यूएस द्विपक्षीय संबंधों में नए अवसर
- सहयोग को प्रोत्साहन: भारत–सऊदी अरब आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए रोडमैप
- भारत का उभरता लिथियम–आयन बैटरी रीसाइक्लिंग बाजार

संपादकीय टीम:
श्री डेविड सिनाटे, *मुख्य महाप्रबंधक*
श्री विश्वनाथ जांध्याला, *सहा. महाप्रबंधक*
सुश्री अल्फिया अंसारी, *उप प्रबंधक*

इंडिया एक्ज़िम बैंक
की तिमाही प्रकाशन

केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई - 400 005.
फोन: 022 2217 2600
ईमेल: ccg@eximbankindia.in
www.eximbankindia.in
www.eximmitra.in

पूर्वी अफ्रीका में भारत के लिए आर्थिक अवसर

अल्फिया अंसारी, *उप प्रबंधक*
कनिष्क चौधरी, *अधिकारी*

अफ्रीकी महाद्वीप में पूर्वी अफ्रीका सबसे डायनैमिक और तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। इसकी वृद्धि 2023 की 3.5% से बढ़कर 2024 में 5.1% और 2025 में 5.7% रहने का अनुमान है। सबसे अधिक अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्वी अफ्रीका की जीडीपी वृद्धि 2023 में 5% से अधिक रही, जो इसके निरंतर अच्छे निष्पादन और विविधीकृत अर्थव्यवस्था को रेखांकित करती है। पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (ईएसी) इस क्षेत्र के 8 देशों– बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआर कांगो), केन्या, रवांडा, दक्षिण सूडान, यूगांडा, तंजानिया और सोमालिया का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय अरुशा, तंजानिया में है।

ईएसी अफ्रीकी संघ के सबसे एकीकृत क्षेत्रीय आर्थिक समूहों में से एक है। ईएसी की जनसंख्या 317.9 मिलियन है। इसमें 30% से अधिक शहरी जनसंख्या है। 2023 में 5.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर के भूमि क्षेत्र और 344.7 बिलियन यूएस डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ ईएसी का बड़ा रणनीतिक और भूराजनीतिक महत्त्व है। 2023 के दौरान सदस्य देशों में रवांडा, डीआर कांगो और केन्या में सबसे अधिक वृद्धि रही, जबकि दक्षिण सूडान में फिर से मंदी रही।

ईएसी देशों के साथ भारत का मर्चेंडाइज व्यापार

भारत और ईएसी के मर्चेंडाइज व्यापार में पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। दोनों का कुल व्यापार 2013 के 9.7 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2022 में 12.9 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया। भारत का ईएसी को निर्यात 2013 के 8.6 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2022 में 9.4 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। ईएसी से भारत का आयात 2013 में मात्र 1 बिलियन यूएस डॉलर का था। तब से आयात में लगातार वृद्धि दर्ज की जाती रही है और 2022 में मर्चेंडाइज आयात 3.5 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। भारत का ईएसी के साथ धनात्मक व्यापार संतुलन है और वर्ष 2022 में 5.8 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार अधिशेष दर्ज किया गया।

वर्ष 2022 में, इस क्षेत्र में भारतीय निर्यातों के लिए तंजानिया 43.6% की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा बाजार रहा। 2022 के दौरान, इस क्षेत्र में भारतीय निर्यात के लिए 31.4% की हिस्सेदारी के साथ केन्या, सोमालिया (9.8%) और डीआर कांगो (6.7%) क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे बड़े निर्यात बाजार रहे।

इस अवधि में ईएसी से भारत का आयात 3.5 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। ईएसी देशों के बीच 80.1% की हिस्सेदारी के साथ तंजानिया भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यातक रहा। 2022 में भारत को निर्यात करने वाले ईएसी के अन्य प्रमुख देशों में यूगांडा (13.1% की हिस्सेदारी के साथ), केन्या (3.5%) और डीआर कांगो (1.6%) शामिल रहे।

वर्ष 2022 में, ईएसी को भारत से निर्यातित प्रमुख मदों में खनिज ईंधन और तेल शामिल रहे, जिनकी 3.2 बिलियन यूएस डॉलर के कुल निर्यात में 33.7% की हिस्सेदारी रही। भारत के लिए अन्य प्रमुख निर्यात श्रेणियों में फार्मासूटिकल उत्पाद (2022 में कुल निर्यात का 10.5%), रेलवे या ट्रामवे के अलावा अन्य वाहन (7.6%), मशीनरी और यांत्रिक उपकरण (6.4%), चीनी और चीनी कन्फेक्शनरी (6.1%) और अनाज (4.4%) शामिल रहे। 2022 में, इस क्षेत्र से भारत के कुल आयात का 40.5% हिस्सा तांबे और इसकी वस्तुओं का रहा। इस अवधि में भारत द्वारा आयातित अन्य उत्पादों में मोती, रत्न और धातु (40.1%), खाद्य फल और मेवा (4.5%), खाद्य सब्जियां (4%), कॉफी, चाय, मेट और मसाले (1.9%) और कोको एवं कोको सामग्री (1.6%) शामिल रहे।

सेवाओं में भारत–ईएसी द्विपक्षीय व्यापार

वर्ष 2021 में, ईएसी को भारत का सेवा निर्यात 943 मिलियन यूएस डॉलर का रहा, जो 2012 के 636 मिलियन यूएस डॉलर से 4% की सीएजीआर से बढ़ता रहा है। वर्ष 2021 में, ईएसी को भारत के निर्यातों में केन्या की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही, जिसे ईएसी को कुल निर्यात का 42.9% निर्यात किया गया। इसके बाद यूगांडा, डीआर कांगो और तंजानिया की हिस्सेदारी रही। ईएसी से भारत का सेवा आयात 2012 के 315 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2021 में 520 मिलियन यूएस डॉलर का रहा, जो 5.1% की सीएजीआर से बढ़ता रहा है। 2021 में इस क्षेत्र से भारत के सेवा आयात में तंजानिया की भागीदारी 49.6% की रही। ईएसी देशों के साथ भारत के सेवा व्यापार में परिवहन और यात्रा सेवाएं प्रमुख रहीं।

भारत और ईएसी के तुलनात्मक लाभ विश्लेषण का परिदृश्य

ईएसी में उत्पादों को उनकी निर्यात स्पर्धात्मकता के आधार पर चिह्नित किया गया है। यह चिह्नीकरण उत्पादों के 6 अंकीय स्तर के एचएस कोड वर्गीकरण के आधार पर विश्लेषण के चार–चतुर्थांश सिद्धांत के जरिए किया गया है। इसमें उनके सामान्यीकृत प्रकट तुलनात्मक लाभ (एनआरसीए) की गणना की गई है और सभी उत्पादों के लिए ईएसी के वैश्विक आयात के एएजीआर के एवज में उनकी मैपिंग की गई है। 2012–2022 के दौरान सभी उत्पादों के लिए ईएसी के वैश्विक आयात के समग्र एएजीआर (जो 9.4% थी) की उसी अवधि के दौरान ईएसी को भारत के निर्यात के एनआरसीए से तुलना कर चतुर्थांश तैयार किया गया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उन उत्पादों को चिह्नित करना है, जिनमें 2012–2021 की अवधि में ईएसी में आयात सभी उत्पादों के लिए ईएसी के समग्र औसत से बेहतर रहा है। इसका अर्थ है कि ईएसी के आयातों में ऐसे उत्पादों की हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की गई है, जो उनकी बढ़ती मांग और गतिशीलता को दर्शाते हैं।

6 अंकीय एचएस कोड पर, भारत से ईएसी को न्यूनतम 1 मिलियन यूएस डॉलर के निर्यात के साथ 577 उत्पादों को चिह्नित किया गया है। यह निर्यात 2022 में 8.5 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, जबकि समान उत्पादों में ईएसी का कुल वैश्विक आयात 55.3 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। एचएस 6–अंकीय स्तर पर 577 मदों में से, 305 मदें उत्पाद चैंपियन श्रेणी में आती हैं। 2022 में भारत से ईएसी को इन मदों का संयुक्त निर्यात 5.7 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। इस प्रकार, 2022 में भारत के निर्यात का लगभग 67.2% ईएसी को रहा। प्रमुख उत्पाद चैंपियनों में खनिज तेल सामग्री, चावल, मोटर कार, मोटरसाइकिल, गेहूं का आटा और मशीनरी आदि शामिल रहे। ये भारत के लिए आसानी से उपलब्ध होने वाले उत्पाद हैं तथा इन्हें अल्पावधि से मध्यम अवधि में लक्षित किया जा सकता है। गिरावट वाले क्षेत्रों की श्रेणी में उत्पादों की कुल संख्या 93 रही, जिसमें भारत का निर्यात 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का रहा और 2022 में ईएसी को भारत के निर्यात में इनकी 18.9% की हिस्सेदारी रही। ये वे उत्पाद मदें हैं, जिनमें ईएसी के आयातों में भारत का महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा है, लेकिन इन उत्पादों के लिए ईएसी की आयात मांग पिछले दशक में गिरी है। इसके बाद 139 मदों के साथ अंडरअचीवर्स श्रेणी के उत्पाद रहे, जिनका भारत से ईएसी को 993.2 मिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया गया। ईएसी को भारत के कुल निर्यात में इन उत्पादों की 11.7% की मामूली हिस्सेदारी रही। ये वे उत्पाद मदें हैं, जिनकी ईएसी में आयात मांग बढ़ रही है, लेकिन इन मदों के निर्यात में भारत की सीमित स्पर्धात्मकता है। अंडरअचीवर्स श्रेणी में मुख्य रूप से हल्के तेल और सामग्री, लोहे या गैर–मिश्र धातु इस्पात के अर्ध–तैयार उत्पाद और स्वचालित यांत्रिक शवल शामिल हैं।

ईएसी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश

ईएसी क्षेत्र में भारत का कुल पूंजीगत निवेश 59 परियोजनाओं के जरिए 1.8 बिलियन यूएस डॉलर की संचयी राशि का रहा और इस क्षेत्र में 9,598 रोजगारों का सृजन हुआ। 2013–2023 के दौरान, केन्या को इस क्षेत्र में भारत के बाह्य प्रत्यक्ष निवेश का 35.8% प्राप्त हुआ। इसके बाद तंजानिया (29.5%), यूगांडा (18.9%), डीआर कांगो (10.7%) और रवांडा (5.2%) को बाह्य प्रत्यक्ष निवेश मिला। 2013–2023 के दौरान, ईएसी देशों में भारत से अनुमोदित निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा (ईएसी को प्राप्त कुल निवेश का 35.1%) संचार क्षेत्र को रहा। इसके बाद परिवहन और भंडारण (9.5%), गैर–मोटर वाहन परिवहन ओईम (7.6%), औद्योगिक उपकरण (6.4%), रियल एस्टेट (6.1%), लीज़र और मनोरंजन (5.9%) और स्वास्थ्य सेवा (5.6%) का स्थान रहा।

2013-2023 के दौरान पिछले एक दशक में ईएसी से भारत में निवेश थोड़ा मंदा रहा। ईएसी द्वारा 12 परियोजनाओं में 748.8 मिलियन यूएस डॉलर का कुल पूंजीगत निवेश किया गया। सभी 12 परियोजनाओं में निवेश मुख्य रूप से केन्या (98.9%) और तंजानिया (1.1%) द्वारा सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं एवं संचार क्षेत्र में किया गया है।

ईएसी देशों में भारत के लिए निवेश के अवसर

पूर्वी अफ्रीका संभावनाओं से भरा क्षेत्र है। यहां कृषि से खनन तक और पर्यटन से ऊर्जा तक विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के प्रचुर अवसर हैं। ईएसी सदस्यों के बीच कोई निवेश करार नहीं है, तथापि उनका उद्देश्य इस क्षेत्र को एकल निवेश क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देना है। 2006 ईएसी मॉडल इन्वेस्ट कोड राष्ट्रीय निवेश नीतियां और कानून बनाने के लिए केवल संदर्भ गाइड के रूप में काम करता है। तथापि, सदस्य देशों पर इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। इसमें विदेशी निवेशकों के राष्ट्रीय व्यवहार और उनके साथ भेदभाव न करने संबंधी प्रावधान हैं। इसके अलावा, इसमें आस्तियों के निःशुल्क हस्तांतरण तथा अप्रतिपूरित अधिग्रहण से सुरक्षा का भी प्रावधान है। भारत के लिए प्रमुख निवेश अवसर निम्नलिखित क्षेत्रों में मौजूद हैं:

- बुरुंडी – अक्षय ऊर्जा और विनिर्माण
- डीआर कांगो – ऊर्जा और खनन
- केन्या – सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र
- रवांडा – कृषि एवं अवसंरचना
- सोमालिया – पशुधन और कृषि
- दक्षिण अफ्रीका – कृषि एवं कृषि व्यवसाय एवं अवसंरचना
- तंजानिया – सूती वस्त्र और अवसंरचना
- यूगांडा – पर्यटन और खनिज मूल्य संवर्धन

आगे क्या

पूर्वी अफ्रीकी समुदाय ने हाल के वर्षों में अपने सहभागी देशों की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने की दिशा में काफी प्रगति की है। हाल के वर्षों में भारत–ईएसी व्यापार और निवेश में धनात्मक प्रगति इस क्षेत्र में भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती रुचि को दर्शाती है। इसलिए ईएसी क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंध बढ़ाने संबंधी रणनीति में एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जिसमें इस क्षेत्र में विकास चुनौतियों का सामना करने और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापार और निवेश से संबंधित विकास एजेंडा शामिल होगा। ईएसी और भारत के बीच सहयोग के लिए रणनीतिक खनिजों में साझेदारी को मजबूत करना, वित्तीय समावेशन को सुगम बनाना, रक्षा सहयोग, फार्मासूटिकल क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल व्यापार एवं अवसंरचना और काउंटर व्यापार अवसर जैसे क्षेत्र शामिल होंगे।

अफ्रीका–भारत भागीदारी दिवस में एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन का विमोचन

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) समूह की वार्षिक बैठक से जुड़े कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में अफ्रीका–भारत भागीदारी दिवस (एआईपीडी) का आयोजन किया। यह कार्यक्रम अफ्रीका के निर्माण में भारत की भूमिका पर केंद्रित रहा। बैंक ने एआईपीडी का आयोजन 2013 में माराकेच से शुरू किया था। इसके बाद किगाली (2014), आबिदजान (2015), लुसाका (2016), अहमदाबाद (2017), अक्रा (2022) और शर्म अल शेख (2023) में यह आयोजन किया गया। एआईपीडी के सभी कार्यक्रम विशेष रूप से सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से भारत के विकास अनुभवों को साझा करने पर केंद्रित थे। इस वर्ष के एआईपीडी में `**पूर्वी अफ्रीका में भारत के लिए आर्थिक अवसर तलाशना**` शीर्षक वाले इंडिया एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन का विमोचन किया गया। इसका विमोचन वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव, डॉ. विवेक जोशी और इंडिया एक्ज़िम बैंक की प्रबंध निदेशक, सुश्री हर्षा बंगारी ने किया। इस प्रकाशन में पिछले दशक के दौरान भारत–पूर्वी अफ्रीका संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है और दोनों भागीदारों के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है। ■

तेलंगाना से निर्यात को बढ़ाना: ट्रेंड और नीतिगत परिदृश्य

– **जाह्नवी सिंह,** *मुख्य प्रबंधक*
नेहा रामन, *प्रबंधक*

तेलंगाना, दक्षिण भारत का एकमात्र बंदरगाह विहीन राज्य है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए विशिष्ट लाभ की स्थिति में है। यह देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक है। इसके जीएसडीपी (स्थिर कीमतों पर) में 2021–22 और 2022–23 के दौरान, भारत के जीडीपी की तुलना में वर्ष–दर–वर्ष अच्छी वृद्धि रही। हाल के वर्षों में तेलंगाना का मर्चैंडाइज निर्यात भी निरंतर बढ़ा है। इसमें 2018–19 से 2022–23 के दौरान 12.3% की अच्छी सीएजीआर दर्ज की गई और 2022–23 में यह 11.4 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। तेलंगाना से मर्चैंडाइज निर्यात कोविड–19 महामारी सहित तमाम बाहरी झटकों से उल्लेखनीय रूप से अप्रभावित रहे। 2019–20 और 2020–21 के दौरान भारत के कुल मर्चैंडाइज निर्यात में जहां गिरावट दर्ज की गई, वहीं तेलंगाना के मर्चैंडाइज निर्यात में क्रमशः 2.7% और 18.3% की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। तेलंगाना का मर्चैंडाइज निर्यात 2021–22 और 2022–23 के दौरान लगातार बढ़ा और इसमें क्रमशः 26.3% और 3.8% की सीएजीआर दर्ज की गई। इस 2022–23 में राज्य का मर्चैंडाइज निर्यात 11.4 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। यह ट्रेंड वित्तीय वर्ष 2023–24 में भी जारी रहा। अप्रैल–दिसंबर 2022–23 के दौरान, तेलंगाना का मर्चैंडाइज निर्यात 9.4 बिलियन यूएस डॉलर रहा, जिसमें 12.1% की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

राज्य में सुदृढ़ वृद्धि, अनुकूल नीतिगत परिवेश और सुदृढ़ परिवहन अवसंरचना के बावजूद, 2022–23 में भारत के मर्चैंडाइज निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी केवल 2.5% रही। इसके अलावा, तेलंगाना के जीएसडीपी (मौजूदा कीमतों पर) में मर्चैंडाइज निर्यात की हिस्सेदारी भी 2022–23 में केवल 6.9% रही, जो 2022–23 में भारत के जीडीपी में मर्चैंडाइज निर्यात की 13.3% की हिस्सेदारी से काफी कम है। ये आंकड़े राज्य से निर्यातों को और बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश का संकेत देते हैं।

मर्चैंडाइज निर्यात के लिए प्रमुख उत्पाद और बाजार

ड्रग फॉर्मूलेशन और बायोलॉजिकल तेलंगाना से सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली उत्पाद श्रेणी है। तेलंगाना के मर्चैंडाइज निर्यात में इनकी 35.2% की हिस्सेदारी है। इसके बाद अवशिष्ट रसायन और संबद्ध उत्पाद (तेलंगाना के मर्चैंडाइज निर्यात में 10.2% की हिस्सेदारी), थोक दवाएं, ड्रग इंटरमीडिएट्स (6.5%), कार्बनिक रसायन (5.7%), मसाले (3.6%) और इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण (3.4%) आदि आते हैं।

तेलंगाना भारत में `अपरिष्कृत उर्वरक' और `फल/ वनस्पति बीजों' का सबसे बड़ा निर्यातक है। 2022–23 के दौरान, भारत के समग्र निर्यातों में इन उत्पादों की हिस्सेदारी क्रमशः 22.9% और 22.1% की रही। तेलंगाना देश में ड्रग फॉर्मूलेशन, बायोलॉजिकल और थोक दवाएं, ड्रग इंटरमीडिएट्स का भी प्रमुख निर्यातक है। 2022–23 के दौरान भारत के समग्र निर्यातों में इनकी हिस्सेदारी क्रमशः 20.7% और 15.7% रही।

तेलंगाना के निर्यातों का सबसे बड़ा आयातक यूएसए है, जिसने 2022–23 के दौरान तेलंगाना से मर्चैंडाइज निर्यात का लगभग 30.0% अकेले ही आयात किया। इसके बाद चीन (5.8% की हिस्सेदारी), यूएई (4.9%), बेल्जियम (3.0%) और यूके (2.5%) आदि प्रमुख आयातक रहे।

तेलंगाना से सेवा निर्यात

एक्ज़िम बैंक के आकलन के अनुसार, भारत से सेवा निर्यात में तेलंगाना का योगदान कम से कम 10% है, जो देश से मर्चैंडाइज निर्यात में राज्य के योगदान से काफी अधिक है। राज्य ने खुद को आईटी और आईटी आधारित सेवा क्षेत्र में खुद को स्थापित किया है। राज्य का आईटी/ आईटी आधारित सेवा निर्यात 2021–22 के ₹ 1,83,579 से 2022–23 के दौरान आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर ₹ 2,41,275 करोड़ पहुंच गया, जिसमें 31.4% की दोहरे अंकों की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। राज्य के गठन के बाद से 2022-23 में ₹ 57,706 करोड़ की वृद्धि आईटी और आईटी आधारित सेवा निर्यात में सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि रही। पर्यटन, राज्य से सेवाओं के निर्यात की अन्य प्रमुख श्रेणी है। विदेशी पर्यटकों की यात्राओं से 2022 के दौरान तेलंगाना की विदेशी मुद्रा आय 135 मिलियन यूएस डॉलर की रही। पर्यटन और आईटी क्षेत्र ने संयुक्त रूप से 2022–23 के दौरान राज्य के लिए 30 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक का निर्यात राजस्व अर्जित किया।

निर्यात संवर्धन रणनीतियां

तेलंगाना को निर्यातों के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए एक सुदृढ़ निर्यात रणनीति अपनाने की जरूरत है। इसमें छह मुख्य आयाम हैं। इनमें उत्पादों और बाजारों का विविधीकरण करना, बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना और उसका सदुपयोग करना, क्षमता विकास, राजकोषीय प्रोत्साहन, निर्यात संवर्धन अभियान तैयार करना और संस्थागत समन्वय शामिल हैं।

लक्षित उत्पादों और बाजारों के लिए विविधीकरण

एक्ज़िम बैंक के विश्लेषण के अनुसार, हालिया अवधि के दौरान राज्य से मर्चैंडाइज निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन यह कुछ उत्पादों तक संकेंद्रित है। तेलंगाना के मर्चैंडाइज निर्यातों के विश्लेषण के अनुसार, 2022–23 के दौरान तेलंगाना से कुल मर्चैंडाइज निर्यात में शीर्ष 10 निर्यात मदों और शीर्ष 10 आयातकों की हिस्सेदारी क्रमशः लगभग 72.1% और 56.4% रही। तेलंगाना के निर्यातकों को अपने निर्यातों में विविधता लाने के लिए उच्च मूल्य–वर्धित क्षेत्रों और कम पहुंच वाले भौगोलिक क्षेत्रों का रुख करने की आवश्यकता है।

इंडिया एक्ज़िम बैंक के विश्लेषण के अनुसार तेलंगाना फार्मासूटिकल; कार्बनिक रसायन; विद्युत मशीनरी एवं उपकरण; कॉफी, चाय, मेट और मसाला; रत्न एवं आभूषण; मशीनरी और यांत्रिक उपकरण; और अनाज आदि में तुलनात्मक लाभ की स्थिति में है। अल्प से मध्यम अवधि में, तेलंगाना इन क्षेत्रों में उभरते अवसरों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, क्योंकि राज्य इनमें लाभ की स्थिति में है।

राज्य को मध्यम से दीर्घावधि में उन क्षेत्रों में क्षमता विकास को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जहां तुलनात्मक अनुकूलता का अभाव है, लेकिन अच्छी वैश्विक मांग बनी हुई है। इनमें अन्य खाद्य सामग्री; रोग प्रतिरोधक उत्पाद; पॉलीथीन प्लेटें और शीटें; प्लास्टिक की वस्तुएं; कारों के लिए नए न्यूमैटिक टायर; गास्केट और वॉशर; टर्बो जेट पुर्जे; गैस टर्बाइन पुर्जे; एयर कंडीशनिंग मशीनों के पुर्जे; स्टेटिक कन्वर्टर; और चिकित्सा उपकरण आदि जैसे कई उच्च मूल्य–वर्धित उत्पाद शामिल हैं। इन उत्पादों को घटती वैश्विक मांग और मूल्य में उतार–चढ़ाव की स्थिति में राज्य के निर्यातों को अनुकूलन बनाए रखने के लिए लक्षित किया जा सकता है।

इसके अलावा, विश्लेषण में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि कई ऐसी चिह्नित उत्पाद श्रेणियां हैं, जिनमें शीर्ष वैश्विक आयातकों के लिए तेलंगाना शीर्ष निर्यातकों में शामिल नहीं है। राज्य के निर्यातकों के लिए जर्मनी, जापान, फ्रांस, सिंगापुर, इटली, नीदरलैंड आदि जैसी कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं सहित प्रमुख वैश्विक बाजारों में पहुंच बनाने की पर्याप्त गुंजाइश है। इन शीर्ष बाजारों में तेलंगाना से उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए बाजार प्रवेश संबंधी रणनीति की आवश्यकता है।

अवसंरचना का सदुपयोग और सुदृढ़ीकरण

राज्य को मौजूदा निर्यात अवसंरचना को उन्नत करने की जरूरत है, जिसमें परिवहन, भंडारण अवसंरचना के साथ–साथ सेवा क्षेत्र के लिए अवसंरचना शामिल है। परिवहन के क्षेत्र में, राज्य को एअर कार्गो सुविधाएं (एसीएफ) और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो स्थापित करने की जरूरत है। फिलहाल, राज्य में केवल 1 एसीएफ और 2 आईसीडी हैं, जो तुलनात्मक आर्थिक आकार वाले कई अन्य दक्षिणी राज्यों और बंदरगाह विहीन राज्यों की तुलना में काफी कम हैं।

इसके अलावा, राज्य से कृषि और संबंद्ध गतिविधियों और फार्मासूटिकल जैसे क्षेत्रों से अच्छे निर्यात को ध्यान में रखते हुए राज्य को गोदामों (वेयरहाउस) और शीत भंडारण (कोल्ड स्टोरेज) क्षमताओं में भी काफी वृद्धि करने की जरूरत है। अन्य राज्यों के साथ तेलंगाना की भंडारण क्षमता की तुलना से पता चलता है कि तेलंगाना में दक्षिणी राज्यों और बंदरगाह विहीन राज्यों में सबसे कम भंडारण क्षमता है। उसी तरह, सबसे कम कोल्ड स्टोरेज क्षमता वाले राज्यों में तेलंगाना दूसरे स्थान पर है। तेलंगाना अपने यहां आईसीडी, सीएफएस, वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और अन्य आवश्यक निर्यात अवसंरचनाओं के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र सरकार की निर्यात संबंधी व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) के तहत सहयोग का उपयोग कर सकता है।

क्षमता विकास

तेलंगाना के कुल 16 उत्पादों को जीआई दर्जा प्राप्त है। इनमें 2 कृषि क्षेत्र से, 1 खाद्य सामग्री और शेष 13 हस्तकला क्षेत्र से संबंधित हैं। तेलंगाना को अपने इन उत्पादों के जीआई दर्जे के साथ इन उत्पादों के लिए एक ब्रांडिंग रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जीआई ब्रांड के तहत मार्केट किए जाने वाले सभी उत्पाद न्यूनतम विशिष्ट मानकों पर खरे उतरें। यह पहल राज्य के ऐसे और उत्पादों के चिह्नीकरण के लिए आवश्यक है, जो जीआई दर्जे के अनुरूप हो सकते हैं। इसमें राज्य के विशिष्ट पाक व्यंजन जैसे `सर्व पिंडी', `सकीनालु', `गोलिचिना ममसम' और `पाची पुलुसु' जैसे पेय पदार्थ आदि शामिल हो सकते हैं। जीआई टैग इन खाद्य पदार्थों की लोकप्रियता को बढ़ा सकता है और इस तरह राज्य से इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। इन तैयार खाद्य पदार्थों के लिए जीआई टैग प्राप्त करना राज्य से पाक पर्यटन के संवर्धन में सहायक हो सकता है।

इसके अलावा, राज्य के निर्यातकों द्वारा निर्यात संवर्धन हेतु सांविधिक प्रमाणन/मान्यता प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान करने पर विचार कर सकता है। उदाहरण के लिए, फार्मासूटिकल निर्यात बढ़ाने के लिए डब्ल्यूएचओ–जीएमपी प्रमाणन और राज्य में उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से निर्यात संवर्धन के लिए कन्फर्माइट यूरोपीन (सीई), चाइना कम्पल्सरी सर्टिफिकेशन (सीसीसी), गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जीएमपी) प्रमाणन आदि पर व्यय की प्रतिपूर्ति पर विचार किया जा सकता है।

राजकोषीय प्रोत्साहन

तेलंगाना में रिफंड / प्रतिपूर्ति और रियायतों के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहन निर्यातकों का लागत भार कम करने और मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। राज्य सरकार राज्य से प्रमुख उत्पादों के निर्यात में बंदरगाह से दूर जिलों पर विशेष फोकस के साथ माल ढुलाई घटक पर सब्सिडी देने के लिए भाड़ा सब्सिडी बढ़ाने पर विचार कर सकती है। इसके अलावा, तेलंगाना सरकार द्वारा विनिर्माताओं, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां हासिल करने और उन्हें विकसित करने, विकास को गति देने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सहयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण सहयोग भी प्रदान किया जा सकता है।

निर्यात संवर्धन अभियान

तेलंगाना को अपने निर्यात संवर्धन अभियान को निरंतर बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार के निर्यात संवर्धन प्रयासों को राज्य के विभिन्न औद्योगिक समूहों पर केंद्रित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, मौजूदा समूहों के मूल्यांकन के लिए एक तंत्र विकसित किया जा सकता है। समूहों के मूल्यांकन के बाद, राज्य सरकार द्वारा संबंधित क्षमता विकास गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य के उत्पादों के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी ब्रांड बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक ब्रांड इक्विटी फंड भी स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य के निर्यातकों की भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए एक राज्य स्तरीय बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना भी शुरू की जा सकती है, ताकि विदेश में व्यापार प्रतिनिधिमंडलों/क्रेता–विक्रेता बैठकों/मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने में निर्यातकों को सहयोग किया जा सके।

संस्थागत समन्वय

राज्य में निर्यात संवर्धन से संबंधित गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए, राज्य में निर्यातकों और हितधारकों के लिए एक एकल मंच आवश्यक होगा। तेलंगाना में समग्र संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र को इस तरह से तैयार करने की आवश्यकता है, जिससे निर्यात के लिए प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं को सुगम बनाया जा सके, ताकि प्रस्तावित लक्ष्यों की नियमित निगरानी की जा सके और इस प्रकार राज्य को उच्च निर्यात पथ पर अग्रसर किया जा सके। इस संदर्भ में, राज्य द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए एक सुदृढ़ संस्थागत तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार के उद्योग विभाग के तहत तेलंगाना निर्यात संवर्धन परिषद (टीईपीसी) की स्थापना की जा सकती है। ■

भारत–यूएस द्विपक्षीय संबंधों में नए अवसर

सिद्धार्थ नेमा, *उप प्रबंधक*
विशाखा भागवत, *अधिकारी*

मुख्यतः सुदृढ़ सेवा क्षेत्र और उच्च उपभोक्ता व्यय की संस्कृति वाली अमेरिकी अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर हावी है। वर्ष 2022 में अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लगभग 25.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ कुल वैश्विक जीडीपी का लगभग 25% रहा। वस्तुतः, सेवा उद्योग अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 2022 में सकल मूल्य संवर्धन में इसका 80% का प्रभावशाली योगदान रहा। वहीं, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 18.3% रहा और कृषि क्षेत्र का मात्र 1.1% का योगदान रहा।

भारत–अमेरिका मर्चैंडाइज व्यापार

भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध फल–फूल रहे हैं। वर्ष 2022 में वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 132 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक रहा। अमेरिका भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण निर्यात बाजार है। भारत के कुल निर्यात का 17.7% अमेरिका द्वारा आयात किया जाता है। 2030 तक 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के वस्तु एवं सेवा निर्यात के लिए भारत के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अमेरिका प्रमुख भूमिका निभा रहा है। अमेरिका की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था व्यापार पर अधिक निर्भर है। भारत का व्यापार अपने सकल घरेलू उत्पाद का 50% है, जबकि अमेरिका का व्यापार उसके सकल घरेलू उत्पाद का 27.4% है। अमेरिका भारत के लिए न केवल सबसे बड़ा आयातक है, बल्कि तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत का अमेरिका को निर्यात 2012 के 37.2 बिलियन यूएस डॉलर से 2022 में तेजी से बढ़कर 80.2 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। इसमें मुख्य रूप से मोती, महंगे रत्न और धातु, फार्मासूटिकल एवं खनिज ईंधन और तेल का निर्यात शामिल रहा। इसके विपरीत, अमेरिका से भारत का आयात भी 2022 में बढ़कर 51.8 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया, जिसमें मशीनरी और बिजली के उपकरणों के साथ–साथ आयातों में समान श्रेणियां प्रमुख रहीं।

भारत–अमेरिका सेवा व्यापार

भारत और अमेरिका वैश्विक सेवा व्यापार में शक्तिशाली केंद्र हैं। 2022 में, अमेरिका दुनिया में सेवाओं के अग्रणी निर्यातकों में सर्वोच्च स्थान पर रहा, जबकि भारत ने सातवें स्थान पर सुदृढ़ स्थिति हासिल की। यह प्रभुत्व सेवा आयात में भी दिखा, जिसमें अमेरिका शीर्ष और भारत नौवें स्थान पर रहा। विशेषकर, भारत और अमेरिका का व्यापार संबंध सेवा क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण है। वर्ष 2022 में भारत अमेरिका के लिए 7वें सबसे बड़े सेवा निर्यातक और 11वें सबसे बड़े सेवा आयातक के रूप में उभरा।

भारत और अमेरिका का कुल सेवा व्यापार 2012 के 29.9 बिलियन यूएस डॉलर से 2022 में बढ़कर 59.1 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। हालांकि, महामारी के कारण इसमें वर्ष–दर–वर्ष 20% से अधिक की उल्लेखनीय गिरावट आई, जिससे 2020 में कुल सेवा व्यापार घटकर 42.5 बिलियन यूएस डॉलर का रह गया। महामारी के बाद, सेवा व्यापार में जोरदार उछाल आया और 2022 में यह 59.1 बिलियन यूएस डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह उछाल अमेरिका द्वारा भारत को निर्यातों के रिकॉर्ड 25.9 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने के चलते रहा। वहीं, अमेरिका द्वारा भारत से आयात 33.2 बिलियन यूएस डॉलर के दर्ज किए गए। उल्लेखनीय है कि अमेरिका का भारत के साथ सेवा व्यापार घाटा लगातार बना हुआ था, जो 2012 में 7.5 बिलियन यूएस डॉलर था और 2021 में 10.5 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया था। 2022 में अंततः यह कम होकर 7.4 बिलियन यूएस डॉलर दर्ज किया गया। अमेरिका से भारत में सेवाओं के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी होती रही है। 2012 में सेवा व्यापार 11.2 बिलियन यूएस डॉलर का था, जो 2022 में बढ़कर 25.9 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। भारत को अमेरिकी निर्यातों में यात्रा सेवाओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक (47.8%) है, जबकि शिक्षा से संबंधित यात्राओं का हिस्सा कुल सेवा निर्यात का 27.6% रहा। अमेरिका द्वारा भारत को किए जाने वाले सेवा निर्यातों में अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाओं तथा वित्तीय सेवाओं के उपयोग संबंधी शुल्क शामिल हैं। "अन्य व्यावसायिक सेवाओं" (10.4%) की व्यापक श्रेणी में, व्यावसायिक और प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रमुख हैं। अमेरिका द्वारा निर्यात की तुलना में भारत से सेवाओं का आयात अधिक रहता है और यह ट्रेंड जारी है। अमेरिका द्वारा सेवा आयात 2012 के 18.7 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2022 में रिकॉर्ड 33.2 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। उल्लेखनीय है कि भारत से सेवा आयात पर महामारी का प्रभाव निर्यात में गिरावट की तुलना में कम रहा। महामारी के बाद की रिकवरी में वर्ष 2022 में आयातों में 14.4% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। 2021 में अमेरिका द्वारा भारत से किए गए अधिकांश सेवा आयात "अन्य वाणिज्यिक सेवाओं" की व्यापक श्रेणी में आते हैं। 2022 के आंकड़ों पर गहराई से गौर करें तो दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना क्षेत्र में कंप्यूटर सेवाएं अग्रणी हैं, जो समस्त सेवा आयातों का 36.3% है। भारत से अमेरिका द्वारा आयात में अन्य व्यावसायिक सेवाओं की उल्लेखनीय हिस्सेदारी (42.9%) है। इस श्रेणी को पेशेवर और प्रबंधन परामर्श (17.6%), अनुसंधान और विकास (13.2%), और तकनीकी, व्यापार–संबंधी और अन्य व्यावसायिक सेवाओं (12.1%) जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

भारत–अमेरिका द्विपक्षीय निवेश

अमेरिका भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत है। 2014 से 2023 के दौरान अमेरिका द्वारा अनुमानतः 131.7 बिलियन यूएस डॉलर का

निवेश भारत में किया गया। साथ ही, इस अवधि के दौरान 1500 से अधिक अमेरिकी कंपनियों ने यहां उपस्थिति दर्ज कराई। इस उल्लेखनीय पूंजी निवेश का लक्ष्य मुख्य रूप से भारतीय सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा क्षेत्र रहा है, जिसमें कुल एफडीआई का 25.9% प्राप्त हुआ। अमेरिकी निवेश के अन्य आकर्षक क्षेत्रों में उपभोक्ता उत्पाद, संचार, वित्तीय सेवाएं और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल रहे। भारत भी अमेरिका में एक उल्लेखनीय निवेशक के रूप में उभरा है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में निवेश की गई परियोजनाओं और कंपनियों की संख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर है। अमेरिका में भारतीय पूंजी मुख्य रूप से धातु क्षेत्र (कुल निवेश का 23.4% हिस्सा) में लगी है। इसके बाद सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा क्षेत्र का स्थान है।

भारत का प्रकटित तुलनात्मक लाभ विश्लेषण और व्यापार क्षमता

सफल द्विपक्षीय व्यापार ऐसे उत्पादों के चिह्ननीकरण में निहित है, जिनमें भारत का तुलनात्मक लाभ अमेरिका की आयात मांग के अनुरूप है। प्रकटित तुलनात्मक लाभ (रिवील्ड कम्पैरेटिव एडवांटेज - आरसीए) किसी देश की निर्यात क्षमता का आकलन करने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है। 2022 में अमेरिका को भारत से 1 मिलियन यूएस डॉलर के न्यूनतम निर्यात मूल्य वाले 6 अंकीय एचएस कोड पर केंद्रित एक विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन में अमेरिका को भारतीय निर्यात में 75.9 बिलियन यूएस डॉलर का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 1,774 उत्पादों को चिह्नित किया गया है। विशेषकर, 2022 में अमेरिका द्वारा इन्हीं उत्पादों का कुल वैश्विक आयात 2,143.5 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया।

उत्पाद चैंपियन (787 मदें): ये उत्पाद अमेरिका को भारत के सबसे प्रतिस्पर्धी निर्यात का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन मदों का संयुक्त निर्यात वर्ष 2022 में 53.5 बिलियन यूएस डॉलर का था, जो अमेरिका को भारत के कुल निर्यात का लगभग 10.3% रहा।

गिरावट वाले क्षेत्रों में चैंपियन (283 मदें): यद्यपि इन उत्पादों के लिए अमेरिकी आयातों में भारत की उल्लेखनीय हिस्सेदारी (2022 में अमेरिका को कुल निर्यात का 13.6 बिलियन यूएस डॉलर या 15.7%) है, लेकिन पिछले एक दशक में इन मदों की आयात मांग में गिरावट आई है।

अंडरअचीवर्स (556 मदें): ये उत्पाद छूटे हुए अवसर को दर्शाते हैं। इन वस्तुओं के लिए अमेरिकी बाजार में आयात मांग बढ़ रही है; तथापि, भारत में इनके निर्यात में उपयुक्त प्रतिस्पर्धात्मकता का अभाव है। इस श्रेणी के अंतर्गत 2022 में भारत से 556 मदों में कुल 7.3 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया गया।

गिरावट वाले क्षेत्र में कमी (148 मदें): 2022 में भारत का अमेरिका को निर्यात 1.7 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, जिसमें 148 मदों को समावेश रहा। गिरावट वाले क्षेत्रों की श्रेणी के अंतर्गत निर्यात की उच्च श्रेणी अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ उन उद्योगों में विविधीकरण की आवश्यकता को उजागर करती है जिनमें भविष्य में निर्यात की अधिक गुंजाइश है।

भारत-अमेरिका टैरिफ विश्लेषण

अमेरिका और भारत की टैरिफ संरचनाएं काफी भिन्न हैं। अमेरिका एक विकसित अर्थव्यवस्था है और वहां सामान्यतः भारत की तुलना में टैरिफ कम हैं। वर्ष 2021 में, भारत से होने वाले लगभग आधे अमेरिकी आयातों पर कोई टैरिफ नहीं लगा, जबकि भारत ने 2021 में अमेरिका से होने वाले अपने आधे से अधिक आयातों पर 1-10% तक टैरिफ लगाया।

अमेरिकी सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जीएसपी) कार्यक्रम के तहत भारतीय निर्यातों को शुल्क-मुक्त लाभ प्रदान किए गए, लेकिन 2019 में इन लाभों को वापस ले लिया गया। इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुओं के प्रवेश पर उच्च टैरिफ लगने लगे। वर्ष 2021 में, अमेरिका को किए जाने वाले लगभग आधे भारतीय निर्यातों पर कोई टैरिफ नहीं लगा, लेकिन जीएसपी हटाए जाने के बाद कई प्रमुख उत्पाद श्रेणियों को मिलने वाला तरजीही लाभ समाप्त हो गया। जीएसपी हटाने के प्रभाव के विश्लेषण से पता चलता है कि 11 भारतीय उत्पाद श्रेणियां (2 अंकों के एचएस-कोड पर) अमेरिकी बाजार में गैर-शून्य टैरिफ की स्थिति में आ गई हैं। इनमें से कुछ श्रेणियों में, जैसे- विमान के पुर्जे, प्लास्टरिंग सामग्री, सीसा और अन्य वस्तुएं तथा कॉर्क उत्पादों के अमेरिका को कुल निर्यात मूल्य में भी गिरावट दर्ज की गई। यह संभवतः जीएसपी हटाने और महामारी संबंधी व्यवधानों के कारण टैरिफ वृद्धि के संयुक्त प्रभाव के कारण हुआ।

विभिन्न देशों के बीच टैरिफ विश्लेषण से पता चलता है कि अमेरिका को निर्यात करने के मामले में मेक्सिको और फिलीपींस जैसे अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत नुकसान की स्थिति में है। मेक्सिको को अमेरिका के साथ अपने एफटीए संबंधों के कारण सभी 96 उत्पाद श्रेणियों में 0% एएचएस टैरिफ प्राप्त है और फिलीपींस को यह लाभ उसकी 24 उत्पाद श्रेणियों (जीएसपी के कारण) पर मिलता है, जबकि भारत को केवल सात उत्पाद श्रेणियों पर 0% एएचएस टैरिफ मिलता है।

आगे की राह और संस्तुतियां

अमेरिका और भारत के आर्थिक संबंधों में वृद्धि की अपार संभानवाएं हैं। दोनों देशों के संबंध आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने से बुने हैं। दोनों देश संबंधित क्षेत्रों में अपनी-अपनी मजबूतियों का लाभ उठाकर और अपने रणनीतिक लक्ष्यों में एकरूपता लाकर दोनों देश साझी समृद्धि और नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं।

सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जीएसपी) में भारत के लाभों को बहाल करने से अमेरिका को भारत के शीर्ष निर्यातों में वृद्धि होगी। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की भारी संख्या (2023 में 4.4 मिलियन से अधिक) का सदुपयोग करते हुए भारत के सॉफ्ट पॉवर और व्यापार संबंधों को और सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत द्वारा मौजूदा उत्पादों के लिए उन्नत मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित कर और जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं की अपनी पेशकश का विस्तार कर अपनी व्यापार स्थिति को सुधारा जा सकता है। व्यापक सहयोग के क्षेत्रों में एक सामाजिक सुरक्षा करार (एसएसए) करना, पारस्परिक मान्यता करार (एमआरए) करना, डिजिटल डेटा संरक्षण और वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) में सहयोग करना, महत्त्वपूर्ण उभरते प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना और संयुक्त ऊर्जा पहल तथा सुरक्षित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाने जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ■

सहयोग को प्रोत्साहन: भारत–सऊदी अरब आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए रोडमैप

श्रीजिता नंदी, *उप प्रबंधक*
विशाखा भागवत, *अधिकारी*

बड़ी युवा आबादी और डायनैमिक निवेश वाला सऊदी अरब 6 देशों के क्षेत्रीय आर्थिक संगठन `खाड़ी सहयोग परिषद' (जीसीसी), संघ में अर्थव्यवस्था और आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। आईएमएफ के अनुसार 2022 में तेल–समृद्ध इस देश का नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 1,108.2 बिलियन यूएस डॉलर और वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.7% रही, जो प्रमुख जी–20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक रही। वर्ष 2022 में तेल क्षेत्र में जहां 15.3% की अच्छी वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, वहीं गैर–तेल क्षेत्र में 2022 में निजी खपत और निवेश के चलते 4.8% की स्थिर वृद्धि रही। खनन, विनिर्माण और यूटिलिटी आधारित उद्योग सऊदी अर्थव्यवस्था का आधार हैं, जिनका 2022 में सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में 56.2% से अधिक का योगदान रहा। इसमें शेष हिस्सा सेवा और कृषि (क्रमशः 41.3% और 2.5%) क्षेत्र का है। वर्ष 2023 में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और वैश्विक स्तर पर भू–राजनीतिक अनिश्चितताओं को देखते हुए वास्तविक GDP वृद्धि दर घटकर 0.8% रह गई।

सऊदी अरब का अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य

सऊदी अरब मर्चैंडाइज और सेवाओं के वैश्विक व्यापार में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ाता रहा है। तेल आधारित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद सऊदी अरब ने अपनी व्यापार गतिविधियों में विविधता लाने में अच्छी प्रगति की है। वर्ष 2022 तक यह वैश्विक रूप से 20वां सबसे बड़ा निर्यातक और 32वां सबसे बड़ा आयात बाजार रहा, जिसका कुल मर्चैंडाइज व्यापार 600 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक का रहा। यह 2013 से 2022 तक स्थिर वृद्धि को दर्शाता है, जिसमें निर्यात 4.9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर (एएजीआर) और आयात 3.1% की एएजीआर से बढ़ रहा है।

जबकि तेल प्रमुख निर्यात (2022 में 80%) बना हुआ है, जिसका हिस्सा धीरे–धीरे गिरता जा रहा है। यह विविधता निर्यातों में अन्य वस्तुओं, जैसे प्लास्टिक, रसायन और उर्वरक की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाती है। इसके विपरीत, उपभोक्ता और औद्योगिक वस्तुओं की मांग के कारण सऊदी अरब के आयातों में अधिक विविधता है। मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, रेलवे के अलावा अन्य वाहन तथा विद्युत मशीनरी और उपकरण आयातित उत्पादों की सूची में सबसे ऊपर हैं, जो देश के विकास के लिए इन संसाधनों की आवश्यकता को दर्शाते हैं। चीन, भारत और जापान शीर्ष आयातक के रूप में उभरे हैं, जबकि 2022 में चीन, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात प्रमुख निर्यातक रहे।

सऊदी अरब का सेवा निर्यात तेजी से बढ़ रहा है (2013–2022 में 24.5% वार्षिक वृद्धि), जो 2022 में 31.9 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। जबकि इसी वर्ष में सेवा आयात 3% की मामूली वृद्धि के साथ 82.8 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया, जिससे सेवा व्यापार घाटा 2013 के 64.8 बिलियन यूएस डॉलर से घटकर 2022 में 50.9 बिलियन यूएस डॉलर का रह गया। सेवाओं में यात्रा सेवा निर्यात सर्वाधिक (74%) रहे और इसके बाद परिवहन का स्थान रहा। आयातों में विविधता परिवहन और यात्रा क्षेत्र के कारण है। इसके बाद व्यावसायिक सेवाओं, निर्माण, बीमा और पेंशन सेवाएं जैसी अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों का स्थान रहा। अमेरिका सबसे बड़ा सेवा व्यापार भागीदार है। इसके बाद शीर्ष व्यापार भागीदारों में क्रमशः चीन, यूएई और यूके शामिल रहे। सेवाओं के लिए भारत 7वां सबसे बड़ा आयातक और 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है।

भारत और सऊदी अरब का व्यापार परिदृश्य

भारत और सऊदी अरब में आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित सुदृढ़ ऐतिहासिक संबंध हैं। वर्ष 2022 में, सऊदी अरब के लिए भारत दूसरे सबसे बड़े आयातक और पांचवें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा, जबकि भारत के लिए सऊदी अरब नौवां सबसे बड़ा आयातक और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक रहा।

दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 2013 के 49 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2022 में 56.3 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। द्विपक्षीय व्यापार में तेल की प्रमुखता के साथ भारत ने सऊदी अरब से कच्चे तेल का आयात किया, जबकि सऊदी अरब ने भारत से प्रसंस्कृत पेट्रोलियम उत्पाद का आयात किया। 2013 से 2022 के बीच सऊदी अरब को भारत के निर्यातों में 5.4% की एएजीआर दर्ज की गई, जबकि आयात तेज गति (8.5% की एएजीआर) से बढ़े। इसके परिणामस्वरूप भारत का व्यापार घाटा 2013 के 24.2 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2022 में 36 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया।

सऊदी अरब के साथ भारत का व्यापार मुख्यतः तेल पर आधारित है। भारतीय निर्यातों में जहां रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की प्रधानता (लगभग 20%) है, वहीं भारत को सऊदी अरब द्वारा मुख्य रूप से कच्चा तेल बेचा जाता है (आयातों का 82%)। तथापि, दोनों में कुछ विविधता है। भारत द्वारा सऊदी अरब को जहां रसायनों, अनाजों, वाहनों और मशीनरी का निर्यात किया जाता है, वहीं भारत द्वारा सऊदी अरब से उर्वरकों, प्लास्टिक और अन्य रसायनों का आयात किया जाता है।

स्थिर वृद्धि के बावजूद, वर्ष 2021 में भारत और सऊदी अरब का सेवा व्यापार 3.8 बिलियन यूएस डॉलर का ही रहा। दिलचस्प बात यह है कि 2021 में भारत 3.3 बिलियन यूएस डॉलर के निर्यात (अपने कुल सेवा निर्यात का 2.1%) एवं मात्र 481 मिलियन यूएस डॉलर के आयात से लगातार अधिशेष में है। भारत के सेवा निर्यातों में तकनीकी विशेषज्ञता (दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में 20.8%) और अवसंरचना सहयोग (परिवहन और कंस्ट्रक्शन) की प्रधानता है। भारत को सऊदी अरब के सेवा निर्यातों में मुख्य रूप से परिवहन (35%), यात्रा एवं अन्य क्षेत्रों में आगे सहयोग की संभावना दिखाई देती है।

सऊदी अरब में विदेशी निवेश ट्रेंड

सऊदी अरब अपने महत्त्वाकांक्षी विजन 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने लिए सक्रिय रूप से विदेशी निवेश को आकर्षित कर रहा है। सऊदी अरब की इस योजना का उद्देश्य अच्छा एफडीआई आकर्षित कर इसे जीडीपी के 5.7% तक बढ़ाने के साथ जीडीपी में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है। एफडीआई आवक में 2022 में गिरावट (7.9 बिलियन यूएस डॉलर) के बावजूद पूंजीगत व्यय प्रवाह 14.5% सीएजीआर की दर से लगातार बढ़ते हुए 2023 में 28.9 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया, जो एक आशाजनक संकेत है। अमेरिका, चीन, यूएई और फ्रांस शीर्ष निवेशक देश हैं, जो रसायन, कोयला/तेल/गैस और रियल एस्टेट में सबसे अधिक निवेश कर रहे हैं।

इस बीच, सऊदी अरब भी एक वैश्विक निवेशक के रूप में उभर रहा है, जो 2022 में 18.8 बिलियन यूएस डॉलर के जावक निवेश के साथ वैश्विक स्तर पर 17वें स्थान पर है। मिस्र, दक्षिण कोरिया और यूएस इस निवेश के शीर्ष प्राप्तकर्ता देश हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोयला/तेल/गैस जहां जावक एफडीआई (42.1% हिस्सेदारी) के लिए प्रमुख लक्ष्य क्षेत्र बना हुआ है, वहीं अक्षय ऊर्जा के लिए उल्लेखनीय आवंटन (33.7 बिलियन यूएस डॉलर) किया गया है, जो एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। पूंजी आकर्षित करने और उसे लगाने पर यह दोहरा फोकस सऊदी अरब की आर्थिक विविधीकरण और वैश्विक निवेश परिदृश्य में खुद को एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

भारत–सऊदी निवेश परिदृश्य

पिछले दशक में, भारत सऊदी अरब में एक प्रमुख निवेशक रहा है, जो 62 परियोजनाओं में 5.4 बिलियन यूएस डॉलर के निवेश (भारत के कुल नियोजित निवेश का 3.1%) के साथ छठे स्थान पर रहा। इसका सबसे अधिक निवेश (74%) धातुओं में रहा, इसके बाद रियल एस्टेट (12.1%) का स्थान रहा। इसके विपरीत, भारत में सऊदी अरब का निवेश 1.1 बिलियन यूएस डॉलर के साथ अपेक्षाकृत मामूली रहा, जो स्रोत के रूप में 19वें स्थान पर था और इसका फोकस न्यूनतर परियोजनाओं पर रहा। सऊदी अरब ने भारत में मुख्य रूप से परिवहन और रसायनों के साथ–साथ ऊर्जा (कोयला, तेल और गैस एवं अक्षय ऊर्जा – 59.6%) में निवेश किया है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में विनिर्माण, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी जैसे कई आकर्षक क्षेत्र उपलब्ध होने के कारण, सऊदी अरब के पास अपने विशाल संसाधनों का सदुपयोग करने और भारत की विकास गाथा में एक प्रमुख भूमिका निभाने का अनूठा अवसर है।

सऊदी अरब के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने की संभावना

भारतीय निर्यातकों द्वारा सऊदी अरब को निर्यात की जाने वाली संभावित मदों को चिह्नित करने के लिए एक विश्लेषण किया गया है। अल्पावधि में, उत्पाद चैंपियंस की श्रेणी में मौजूदा उत्पादों को सुदृढ़ करने का सुझाव दिया गया है ताकि उन उत्पादों की पूरी क्षमता को भुनाया जा सके, जिनकी वृद्धि सऊदी अरब में पहले से ही अच्छी है और जिनमें भारत को अपने निर्यातों में तुलनात्मक लाभ हासिल है। इनमें मुख्य रूप से चावल, यात्री वाहन, माल वाहन, इंजन और टायर जैसे वाहन के पुर्जे, फ्रोजन बोनलेस गोजातीय मांस, सरैमिक वस्तुएं, तांबा/एल्यूमीनियम के तार, रासायनिक यौगिक, सूती टी–शर्ट आदि शामिल हैं। मध्यम से दीर्घावधि में, इन उत्पादों में क्षमता विकास के लिए अंडरअचीवर्स श्रेणी के उत्पादों में प्रयासों और निवेश को बढ़ाया जा सकता है, जो सऊदी अरब की मांगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तरीके से पूरा करने में मदद करेंगे। इनमें हल्का तेल और इसकी सामग्री, वायरलेस नेटवर्क के लिए स्मार्टफोन, आभूषण सामग्री, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, मक्खन, महिलाओं के कपड़े, एयर कंडीशन मशीन, बिजली के उपकरण, चॉकलेट और प्लास्टिक के सामान, वाणिज्यिक वाहन शामिल हैं।

आगे की राह और संस्तुतियां

भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक संबंध आशाजनक हैं। दोनों अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही हैं और सऊदी अरब का तेल निर्भरता से दूर जाना किफायती तकनीक में भारत की मजबूती के अनुकूल है। वर्तमान में, भारत सऊदी अरब को विनिर्मित वस्तुओं और रिफाइंड तेल का निर्यात और वहां से तेल एवं रसायनों का आयात करता है। भारत व्यापार संतुलन (वर्तमान में सऊदी अरब की ओर झुका हुआ) सुधारने के लिए अपने प्रतिस्पर्धी उत्पादों के निर्यात विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। सऊदी अरब की बढ़ती अर्थव्यवस्था भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुओं और आईटी एवं निर्माण जैसी सेवाओं के लिए एक अच्छा बाजार उपलब्ध कराती है।

दोनों देशों में सहयोग की और संभावनाएं हैं। सऊदी अरब ट्रांज़ैक्शन को सरल बनाने और व्यापार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए भारत के साथ स्थानीय मुद्रा में निपटान पर विचार कर सकता है। अधिशेष मुद्रा का उपयोग आपसी सहमति वाले क्षेत्रों में विभिन्न निवेश अवसरों के लिए किया जा सकता है। पेशेवर योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता से कुशल श्रमिकों का आवागमन आसान हो हो सकता है। इसके अतिरिक्त, दोनों देश अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों का सदुपयोग करते हुए अफ्रीका में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में भागीदार बन सकते हैं। अंततः, स्वास्थ्य सेवा, कृषि–प्रौद्योगिकी (एग्रीटेक) और प्रसंस्कृत खाद्य एवं अक्षय ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम और तकनीकी सहयोग से दोनों अर्थव्यवस्थाएं लाभान्वित हो सकती हैं। साथ ही, मिलकर काम करते हुए भारत और सऊदी अरब पारस्परिक रूप से लाभप्रद आर्थिक साझेदारी बना सकते हैं। ■

भारत का उभरता लिथियम–आयन बैटरी रीसाइक्लिंग बाजार

– **राहुल मजूमदार,** *उप महाप्रबंधक*
धितीका शाह, *अधिकारी*

लिथियम–आयन बैटरी आज दुनिया में सर्वव्यापी हो गई हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और ग्रिड–स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों तक के लिए जरूरी हैं। बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट के संबंध में दुनिया भर में बढ़ती चिंता के साथ, उम्मीद जताई जा रही है कि विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से सड़क परिवहन के डीकार्बनाइजेशन में मदद मिलेगी और हरित ऊर्जा की ओर परिवर्तन में इसकी अहम भूमिका होगी। तथापि, लिथियम–आयन बैटरियों के उपयोग से खतरनाक अपशिष्ट भी निकलता है और इन बैटरियों का लाइफसाइकल भी सीमित होता है, जिस कारण अंततः उन्हें बदलना पड़ता है। इससे बैटरी रीसाइक्लिंग और पुनः उपयोग की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

लिथियम बैटरियों को प्रभावी प्रक्रियाओं के माध्यम से रीसाइकल करने के परिणामस्वरूप मूल्यवान खनिजों का निष्कर्षण होता है और स्वच्छ ऊर्जा के बढ़ते उपयोग को देखते हुए इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार, प्रयुक्त बैटरियों की रीसाइक्लिंग, अन्य के साथ–साथ, निपटान के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, महत्त्वपूर्ण खनिजों के संरक्षण, तथा नई सामग्रियों के निष्कर्षण को कम करने के लिए आवश्यक हो जाता है।

लिथियम–आयन बैटरी रीसाइक्लिंग प्रक्रिया

बैटरियों की छंटाई एवं पृथक्करण	• मैनुअल रूप से या स्वचालित मशीनों की मदद से छंटाई की जाती है
क्रशिंग और टुकड़े करना	• सेलों के आकार को कम करने और बाद की प्रक्रिया के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए
एसिड लीचिंग	• क्रश्ड बैटरी सेलों से ब्लैक मास निकालना
फिल्टरेशन और पृथक्करण	• फिल्टर किए गए घोल में लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज़ और एल्युमीनियम सहित धातु आयन शामिल होते हैं
प्रवण और रिकवरी	• फिल्टर किए गए घोल से धातुओं की रिकवरी के लिए
सुखाना और रोस्ट करना	• यौगिकों या ऑक्साइडों से शुद्ध धातु प्राप्त करना
धातु शोधन और रीसाइक्लिंग	• पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त उच्च गुणवत्ता वाली धातुएं प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस या गलाने जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है

बैटरी रीसाइक्लिंग के महत्त्वपूर्ण चरणों में से एक है, ब्लैक मास का निर्माण, जो कैथोड सक्रिय पदार्थों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राथमिक धातुओं लिथियम, निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज से समृद्ध होता है। ब्लैक मास से धातुओं को रिकवर करने के लिए उपयोग की जाने वाली दो प्राथमिक विधियां हैं। एक है ऊष्मा–आधारित गलाने की प्रक्रिया (पायरोमेटेलर्जी) और दूसरी है, तरल–आधारित लीचिंग प्रक्रिया (हाइड्रोमेटेलर्जी)।

चुनिंदा धातुओं की रिकवरी

	प्राकृतिक संसाधन	रीसाइकल्ड बैटरी
एक टन बैटरी ग्रेड कोबाल्ट से प्राप्त	200 टन अयस्क	5-15 टन रीसाइकल्ड लिथियम आयन बैटरियां
एक टन बैटरी ग्रेड लिथियम से प्राप्त	250 टन अयस्क और 750 टन ब्राइन	28 टन लिथियम-आयन बैटरियां

स्रोतः यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी व्हीकल टेक्नोलॉजीज़ ऑफिस

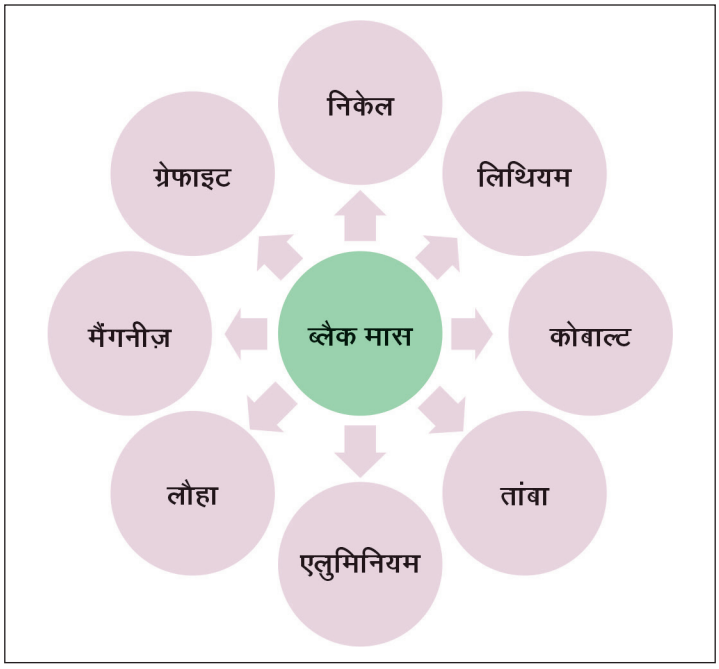

बैटरी रीसाइक्लिंग बाजार

वैश्विक

वर्ष 2023 में वैश्विक लिथियम–ऑयन बैटरी रीसाइक्लिंग बाजार 9.4 बिलियन यूएस डॉलर का था और 2031 तक इसके 8.6% की सीएजीआर से बढ़कर 18.1 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। बाजार में यह वृद्धि ई.वी., पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स और अक्षय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की बढ़ती मांग के कारण हुई है।

वैश्विक स्तर पर लिथियम–आयन बैटरी रीसाइक्लिंग बाजार

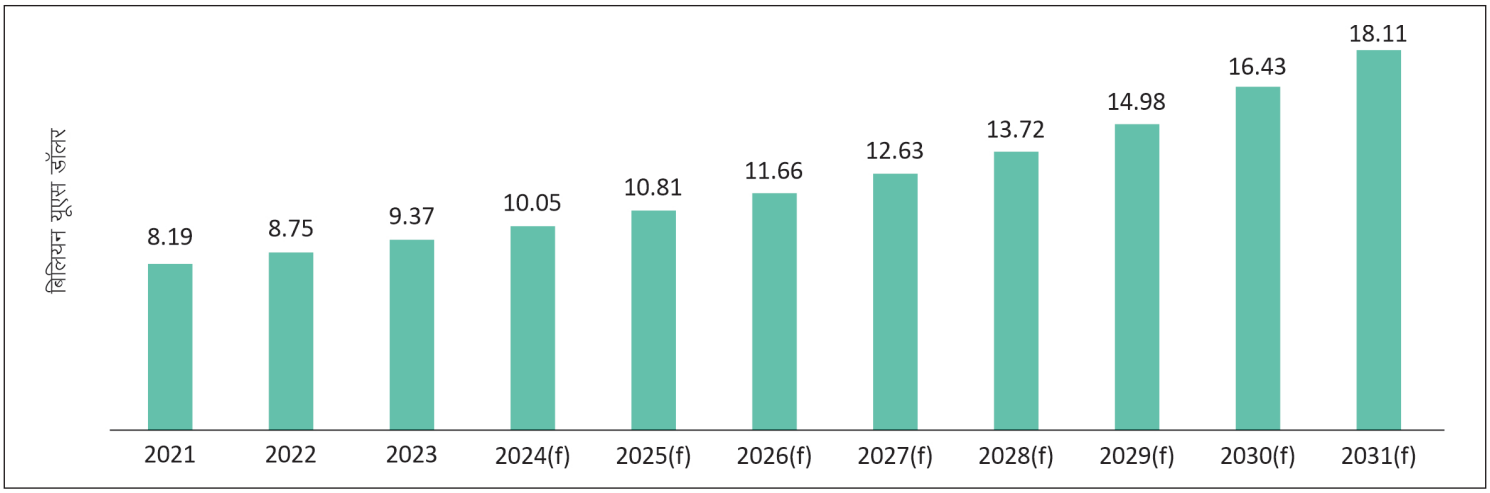

वैश्विक स्तर पर चीन, दक्षिण कोरिया और जापान लिथियम–आयन बैटरियों की रीसाइक्लिंग में अग्रणी हैं। दिसंबर 2023 तक चीन की बैटरी रीसाइक्लिंग क्षमता 500 हजार टन, अमेरिका की 200 हजार टन और यूरोप की 200 हजार टन की थी।

भारत

ईवी कार्यक्रम को बढ़ाने और स्थानीय विनिर्माण को मजबूत करने की भारत की महत्त्वाकांक्षा के सामने बैटरी सेल उत्पादन के लिए पर्याप्त कच्चे माल तक पहुंच सुनिश्चित करने की चुनौती है। वर्तमान में लिथियम–आयन बैटरी और सेल के लिए आयात पर निर्भरता काफी अधिक है, क्योंकि स्थानीय सेल विनिर्माण सीमित है।

भारत का लिथियम आयात, जिसमें लिथियम ऑक्साइड और हाइड्रॉक्साइड (एचएस 282520), लिथियम सेल और बैटरी (एचएस 850650) और लिथियम–आयन एक्युमुलेटर (एचएस 850760) जैसे उत्पाद शामिल हैं, 2018 के 1.2 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2022 में 2.7 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। लिथियम–आयन एक्युमुलेटर अधिकांशतः चीन से मंगाए जाते हैं और 2022 में कुल आयात का 73% हिस्सा चीन से ही आयात हुआ। यह भारत के ईवी उद्योग को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितताओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। इस प्रकार, लिथियम–आयन बैटरियों को रीसाइकल करना भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्त्वपूर्ण घटक बन गया है।

नीति आयोग के अनुसार, 2022–30 के दौरान, भारत में लिथियम–आयन बैटरियों की संचयी क्षमता बेस केस परिदृश्य के तहत सभी खंडों में लगभग 600 GWh होने की उम्मीद है, और 2030 तक इन बैटरियों की रीसाइक्लिंग की मात्रा 128 GWh होगी। इसमें से लगभग 59 GWh या 46% मात्रा अकेले इलेक्ट्रिक वाहनों से होगी।

भारत की वर्तमान रीसाइक्लिंग क्षमता 30,000 टन से भी कम है। एशियाई देशों में बैटरी रीसाइक्लिंग में इसकी सफलता को देखते हुए बाजार का रुख हाइड्रोमेटेलर्जी रीसाइक्लिंग की ओर है।[1] जेएमके रिसर्च के अनुसार, भारत का लिथियम–आयन बैटरी बाजार 2030 तक 132 GWh तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे बैटरी रीसाइक्लिंग क्षेत्र 1 बिलियन यूएस डॉलर का होगा।

वृद्धि के कारक

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती बिक्री इस क्षेत्र के विकास में एक प्रमुख कारक हो सकती है। 2022–2030 के दौरान अनुमानतः 447–517 हजार टन अपशिष्ट बैटरियों के रीसाइक्लिंग फर्मों तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के माध्यम से रीसाइक्लिंग बाजार को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रही है। ये नियम 2026–27 तक 90% सामग्री की रिकवरी के लक्ष्य के साथ अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह और रीसाइक्लिंग/नवीनीकरण के लिए जो वर्ष 2026–27 तक सामग्री की 90% रिकवरी के लक्ष्य के साथ विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू करते हैं।

वृद्धि के अन्य कारकों में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 शामिल है, जिसका उद्देश्य हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है, तथा उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को बढ़ावा देना है, जो बैटरी के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देती है।

उभरता लिथियम–आयन बैटरी बाजार

स्वच्छ ऊर्जा की ओर तीव्र परिवर्तन के कारण भारत का लिथियम–आयन बैटरी बाजार 2024 के अनुमानित 4.7 बिलियन यूएस डॉलर से 2029 में 13.1 बिलियन यूएस डॉलर का होने की उम्मीद है।

वर्तमान में भारत में लिथियम–आयन बैटरी रीसाइक्लिंग उद्योग जहां प्रारंभिक अवस्था में है, वहीं यह ईवी, अक्षय ऊर्जा भंडारण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ती मांग के कारण विस्तार के मुहाने पर भी है। भारत के संपोषी ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक सुदृढ़, औपचारिक बैटरी रीसाइक्लिंग उद्योग आवश्यक है। उम्मीद है कि भारत 2027–2030 तक बड़ी रीसाइक्लिंग क्षमता हासिल कर लेगा। ■

[1] नीति आयोग

इंडिया एक्ज़िम बैंक की ऋण–व्यवस्थाएं

सौजन्य : **ऋण–व्यवस्था समूह**

भारत सरकार ने अन्य के साथ-साथ विशेष रूप से विकासशील देशों के साथ भारत के व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2003-04 के आम बजट के जरिए भारत विकास पहल (आईडीआई) की शुरुआत की थी। इसे बाद में भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आइडियाज़) नाम दिया गया। इस योजना का उद्देश्य विदेश में भारत के रणनीतिक, राजनैतिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देना है। इस संबंध में भारत विकासशील देशों के साथ क्षमता निर्माण और कौशल हस्तांतरण, व्यापार तथा बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए अपने विकास अनुभव साझा करता है और इस तरह स्वयं को उभरती आर्थिक शक्ति और निवेशक देश और विकासशील देशों के लिए एक सहभागी के रूप में स्थापित करता है। बैंक पॉलिसी संस्था के रूप में इस `आइडियाज़' योजना के तहत दूसरे देशों को प्रदत्त ऋण व्यवस्थाओं के लिए एक वित्तपोषण के माध्यम का काम करता है।

नवीनतम `आइडियाज़' दिशानिर्देश संशोधित किए गए हैं। ये 31 मार्च, 2022 से प्रभावी हैं। संशोधित `आइडियाज़' दिशानिर्देशों के तहत, भारत सरकार की रियायती वित्तपोषण योजना (सीएफएस) को इस योजना में मिला दिया गया है। इसमें भारत सरकार रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण विदेशी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय इकाईयों को सहयोग करने के लिए ऋण सहायता लेने वाली किसी भी सरकार या सरकार के स्वामित्त्व या नियंत्रण वाली इकाई को रियायती वित्तपोषण प्रदान करती है। यह वित्त तब प्रदान किया जाता है, जब उक्त भारतीय इकाई ऐसी किसी विदेशी इकाई द्वारा टेंडर की गई परियोजना के निष्पादन का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर लेती है। इस वित्तपोषण के लिए पात्र परियोजना का रणनीतिक महत्त्व भारत सरकार द्वारा मामले वार आधार पर तय किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा संप्रभु सरकारों या उनकी नामित एजेंसियों को दी जाने वाली ऋण सहायताएं वित्तीय वर्ष 2003-04 से भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) द्वारा प्रदान की जा रही हैं। ऋण–व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातकों को नए भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश करने या मौजूदा निर्यात बाजारों में अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सहायक हैं और वह भी विदेशी आयातक से बिना किसी भुगतान जोखिम के। बैंक भारतीय निर्यातकों के लिए किसी बाजार में प्रवेश के एक प्रभावी माध्यम के साथ–साथ बाजार विविधीकरण के साधन के रूप में ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान करने पर विशेष जोर देता है। ये ऋण–व्यवस्थाएं बड़े पैमाने पर जटिल परियोजनाओं (भारत से परियोजना निर्यात) के लिए सहभागी देशों को प्रदान की जा रही हैं।

इंडिया एक्ज़िम बैंक, इन ऋण–व्यवस्थाओं के जरिए उन देशों के क्रेताओं को भारत से विकासपरक और बुनियादी ढांचागत व्यवस्थाएं परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं तथा सेवाएं आयात करने में सक्षम कर सके इसलिए संप्रभु सरकारों, विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों और नामित सरकारी विदेशी इकाइयों को ऋण–व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान करता है। ऋण–व्यवस्थाएं किसे दी जाएंगी, उसकी राशि, शर्तें और उसके उद्देश्य का निर्णय भारत सरकार लेती है। भारत सरकार के परिचालन माध्यम के रूप में इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा इन ऋण-व्यवस्थाओं का वित्त पोषण, संचालन और निगरानी की जाती है।

इंडिया एक्ज़िम बैंक इन ऋण व्यवस्थाओं के तहत एफओबी/सीएफआर/सीआईएफ/सीआईपी आधार पर भारतीय निर्यातकों को कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के 100% की प्रतिपूर्ति करता है। इन ऋण सहायताओं के अंतर्गत कवर किए जाने वाले कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य की न्यूनतम 75% (मामले वार आधार पर 10% की छूट दी जा सकती है) वस्तुएं और सेवाएं (सलाहकार सेवाएं मिलाकर) भारत से आयात की जानी चाहिए। इन ऋण-व्यवस्थाओं से उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता का प्रदर्शित करने में मदद मिली है। इसके अलावा ये ऋण-व्यवस्थाओं हाल के वर्षों में विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस के विकासशील देशों में अनुकूल परिवेश बनाने में मददगार साबित हुई हैं। । इन ऋण-व्यवस्थाओं से भारत के राजनैतिक, रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने के साथ ही लाभार्थी देशों में भारत के प्रति राजनीतिक सद्भाव के विकास में भी मदद मिली है। साथ ही, ऋण-व्यवस्थाएं भारत की बढ़ती आर्थिक सुदृढ़ता के साथ-साथ प्राप्तकर्ता विकासशील देशों में बुनियादी ढांचागत के विकास और क्षमता निर्माण में योगदान करने की भारत की इच्छा को प्रदर्शित करने में भी मददगार हैं। भारतीय निर्यातक शिपिंग दस्तावेजों / सेवाओं के प्रावधान (अनुमोदित भुगतान शर्तों के अनुसार) निगोशीएशन के जरिए क्रेता या क्रेता के देश पर जोखिम के बिना इंडिया एक्ज़िम बैंक से पात्र मूल्य का भुगतान प्राप्त करते हैं।

बैंक द्वारा यथा 30 जून, 2024 को अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस के 68 से अधिक देशों को 27.30 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 293 ऋण व्यवस्थाएं प्रदान की गईं, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण–व्यवस्थाएं भारत से परियोजनाओं, वस्तु और सेवाओं के निर्यात के संवर्धन, सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क कीजिए :

श्री संजय लांबा
उप महाप्रबंधक,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक, ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 1, 7वीं मंज़िल,
रिंग रोड के नजदीक, किदवई नगर (पूर्व)
नई दिल्ली-110023,
फोनः (011) 24607700
ईमेलः eximloc@eximbankindia.in

तिमाही गतिविधियां

सौजन्य : **कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ग्रुप**

62% बढ़ा एक्ज़िम बैंक का मुनाफा, कॉर्पोरेट ऋण में 49% की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि; 17% बढ़ी ऋण आस्तियां

इंडिया एक्ज़िम बैंक की प्रबंध निदेशक, सुश्री हर्षा बंगारी और उप प्रबंध निदेशक, श्री तरुण शर्मा ने सोमवार, 13 मई, 2024 को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक के वित्तीय परिणामों की घोषणा की। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक के वित्तीय परिणामों की खास बातें निम्नलिखित अनुसार हैं:

वित्तीय कार्य निष्पादन

मानदंड	2022–23 में निष्पादन	2023–24 में निष्पादन	2022–23 से परिवर्तन
A. कुल व्यवसाय (₹ करोड़)	2,92,257	3,44,182	17.77%
- निवल ऋण पोर्टफोलियो	1,34,523	1,57,602	17.16%
- कुल उधारियां	1,28,423	1,54,611	20.39%
B. परिचालन लाभ (₹ करोड़)	3,599	3,750	4.20%
C. कर पश्चात लाभ (₹ करोड़)	1,556	2,518	61.83%
D. सकल अनर्जक आस्तियां	4.09%	1.93%	(216) bps
E. निवल अनर्जक आस्तियां	0.71%	0.29%	(42) bps
F. जोखिम भारित पूंजी आस्ति अनुपात	25.43%	21.18%	(425) bps

व्यवसाय निष्पादन

बैंक ने प्रमुख व्यवसाय निष्पादन मानदंडों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो भारत के व्यापार और निवेश तथा मित्र देशों की विकास प्राथमिकताओं को सहायता प्रदान करने की बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत की विकास यात्रा और ऋण की बढ़ी मांग के बीच, बैंक ने ₹1,06,312 करोड़ के नए ऋणों को मंजूरी दी। वित्तीय वर्ष 2023–24 में ऋण पोर्टफोलियो में 17% वृद्धि दर्ज की गई। यह बढ़ोत्तरी स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा, ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग वस्तुओं, फार्मासूटिकल्स और टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि के चलते दर्ज की गई। बैंक ने ई–मोबिलिटी, हाई–टेक और एयरोस्पेस जैसे रणनीतिक महत्त्व के क्षेत्रों में भी वृद्धि दर्ज की। वित्तीय वर्ष 2023–24 में निवल ब्याज आय 4.6% बढ़कर ₹3,540 करोड़ हो गई। यह बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से ऋणों और अग्रिमों से होने वाली ब्याज आय में उच्चतर वृद्धि के चलते दर्ज की गई। अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के मामले में, बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ और स्लिपेज में भी कमी आई। सकल और निवल एनपीए में भी गिरावट आई। सकल एनपीए यथा 31 मार्च, 2023 के 4.09% से घटकर यथा 31 मार्च, 2024 को 1.93% हो गया। वहीं, निवल एनपीए यथा 31 मार्च, 2023 के 0.71% से घटकर यथा 31 मार्च, 2024 को 0.29% हो गया।

"मुक्त व्यापार करारों में वित्तीय सेवाएं" विषय पर कार्यशाला

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने "मुक्त व्यापार करारों में वित्तीय सेवाएं" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया कि एफटीए वार्ताओं के संदर्भ में वित्तीय सेवाओं की भूमिका और वैश्विक व्यापार और आर्थिक विकास पर इनके संभावित प्रभावों पर खुलकर चर्चा की जा सके और इस संबंध में एक बेहतर समझ बने।

कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। इस दौरान, डॉ. जोशी ने भारत के महत्त्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य को रेखांकित किया और कहा कि इसे हासिल करने में भारत की निर्यात रणनीति में वित्तीय सेवाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। साथ ही, उन्होंने इस दिशा में शिक्षाविदों और विषय विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करते हुए निगोशिएटिंग क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि एक्ज़िम बैंक, भारत सरकार के साथ मिलकर काम करते हुए इस प्रयास में योगदान दे सकता है।

कार्यशाला के दौरान, इंडिया एक्ज़िम बैंक की एक ई–बुक "अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज़: ए गाइड टू निगोशिएटिंग फायनैंशल सर्विसेज़ इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स" का भी विमोचन किया गया। इसमें मुक्त व्यापार करारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को कवर किया गया है। यह कार्यशाला, एफटीए के दायरे में वित्तीय सेवाओं के बहुमुखी आयामों पर एक बेहतर समझ बनाने के क्रम में निरंतर कार्यशील रहने और सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुई।

केन्या के नैरोबी में इंडिया एक्ज़िम बैंक के पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय का शुभारंभ

केन्या के नैरोबी में 31 मई, 2024 को भारतीय निर्यात–आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) के पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय का शुभारंभ हो गया। इस दौरान केन्या के माननीय प्रधान कैबिनेट सचिव और विदेश व प्रवासी मामलों के कैबिनेट सचिव डॉ. मूसालिया मुडावडी तथा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव, डॉ. विवेक जोशी, केन्या में भारत की माननीय उच्चायुक्त सुश्री नाम्या सी खाम्पा, और इंडिया एक्ज़िम बैंक की प्रबंध निदेशक, सुश्री हर्षा बंगारी उपस्थित रहीं।

इंडिया एक्ज़िम बैंक एक शीर्ष वित्तीय संस्था है, जो भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के वित्तपोषण, सुगमीकरण और संवर्धन में प्रवृत्त है। साथ ही, बैंक भारत के आर्थिक राजनयिक संबंधों के तहत नीति निर्माण और परियोजना निर्यात वित्त में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक के कार्यालय केन्या के अलावा, आबिदजान, कोत दि`वार और जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में भी हैं।

परस्पर व्यापार और निवेश को सहयोग और बढ़ावा देने के क्रम में, अफ्रीकी महाद्वीप पर फोकस करना इंडिया एक्ज़िम बैंक की रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। बैंक, अफ्रीका में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सहभागी संस्था के रूप में प्रयासरत है, और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ संबंधों को और सुदृढ़ करने की यह प्रतिबद्धता बैंक की गतिविधियों और कार्यक्रमों में भी दिखाई देती है। ■

विभिन्न देशों का आर्थिक परिदृश्य

सौजन्य: **शोध एवं विश्लेषण समूह**

मेक्सिको

जून 2024 में सुश्री क्लाउडिया शिनबाम संयुक्त मेक्सिकन राज्य की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गईं। उन्होंने एंड्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्राडोर का स्थान लिया। अगले प्रशासन में अच्छे शासन और नीतिगत निरंतरता की उम्मीद के बावजूद, 2024 में मेक्सिको की अर्थव्यवस्था में 2.3% की मध्यम वृद्धि का अनुमान है, जो 2023 की 3.2% की वृद्धि दर से कम है। यह मंदी मेक्सिको के मुख्य व्यापार भागीदार यूएस की अर्थव्यवस्था में कम निवेश और मंदी के कारण रही। सेवा क्षेत्र का निष्पादन भी सुस्त रहने का अनुमान है। तथापि, अनुकूल मौसम की स्थिति और स्थिर वैश्विक कमोडिटी कीमतों को देखते हुए मुद्रास्फीति पिछले वर्ष के 5.5% से घटकर 2024 में 4.5% होने का अनुमान है। मैक्सिकन पेसो उभरते बाजारों की सबसे सुदृढ़ मुद्राओं में से एक बनी हुई है, जो धनात्मक जीडीपी वृद्धि से समर्थित है। तथापि, 2024 में PS17.2:US$1 के अनुपात में अवमूल्यन होने की आशंका है। यूएस के साथ उत्पादकता अंतर बढ़ने के कारण इस अवमूल्यन के 2028 तक जारी रहने की आशंका है। बढ़ती यूएस मांग के कारण 2024 की दूसरी छमाही के दौरान निर्यात में संभावित वृद्धि के बावजूद, चालू खाता घाटा जीडीपी के 0.3% पर प्रबंधनीय सीमा के भीतर रहने का अनुमान है।

ब्राज़ील

ब्राज़ील दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तथापि, इसे उच्च सार्वजनिक ऋण/जीडीपी अनुपात और धीमी वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। 2024 में आर्थिक वृद्धि दर (2023 की 2.9% से) कम होकर 2% तक रहने की आशंका है। यह गिरावट 2021–23 में ब्राज़ील सेंट्रल बैंक (बीसीबी) के आक्रामक मौद्रिक–सख्ती के प्रभावों के कारण रहेगी। अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में विनाशकारी बाढ़ के परिणामस्वरूप, कृषि और औद्योगिक उत्पादन में कमी आएगी और पुनर्निर्माण एवं राहत पर भारी सरकारी खर्च से इसका प्रभाव केवल आंशिक रूप से ही कम हो सकेगा। हेडलाइन मुद्रास्फीति (अप्रैल 2024 में 3.7%) बीसीबी की 1.5-4.5% लक्ष्य सीमा के भीतर है। आपूर्ति संबंधी आघातों को छोड़कर, अगले 2 वर्षों में मुद्रास्फीति में और कमी आने की उम्मीद है। यद्यपि ब्राजील का चालू खाता घाटा काफी अधिक है, तथापि इसके संरचनात्मक व्यापार अधिशेष (जो विशाल कृषि निर्यात से उत्पन्न होता है) मामूली बाह्य ऋण अनुपात, अच्छे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह और पर्याप्त आरक्षित निधियों से किसी भी बाह्य स्थिति का जोखिम सीमित रहेगा। ब्राजील की मुद्रा "रियाल" को बीसीबी की मौद्रिक–नरमी और सरकार के कम राजकोषीय लक्ष्यों के कारण दबाव का सामना करना पड़ता है। यह दबाव सितंबर में अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा अपनी पॉलिसी दरें घटाने पर कम हो सकता है।

दक्षिण अफ्रीका

मई 2024 में हुए 7वें राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जो दक्षिण अफ्रीका में एक नई गठबंधन सरकार का संकेत देता है। कुछ प्रमुख नीतिगत परिवर्तनों के अनुमान के साथ, 2024 में आर्थिक वृद्धि दर 1.6% तक बढ़ने का पूर्वानुमान है। यह बढ़ोत्तरी बेहतर मौसम और आसान ऋण पहुंच के चलते संभावित रूप से सुदृढ़ दूसरी छमाही के कारण होगी। नए घरेलू और वैश्विक आघातों को छोड़कर, नियंत्रित मौद्रिक नीति के साथ मुद्रास्फीति घटकर 4.8% होने की उम्मीद है। तथापि, पहली छमाही में उच्च ब्याज दरों और उपभोक्ता व्यय में कमी के कारण वृद्धि में मंदी की आशंका है। मजबूत डॉलर, उच्च यूएस दरों और वैश्विक मंदी को दर्शाते खनिज निर्यात कीमतों में नरमी के कारण 2024 (R18.8:US$1) में रैंड के और कमजोर होने का अनुमान है। कमोडिटी पर निर्भरता, व्यापक रूप से ट्रेड की जाने वाली मुद्रा के रूप में इसकी स्थिति तथा उभरते बाजारों की प्रतिनिधि मुद्रा के रूप में इसकी भूमिका के कारण प्रतिकूल वैश्विक घटनाक्रमों के प्रति रैंड का जोखिम बना रह सकता है। इसके अलावा, 2024 में चालू खाता घाटा जीडीपी का 2% तक घटने की उम्मीद है। क्योंकि कमोडिटी की कीमतें कमजोर वैश्विक वृद्धि और बढ़ते भू–राजनीतिक तनाव के कारण दबाव में हैं, जो निर्यात और आयात के लिए व्यापार प्रवाह को बाधित करेंगी।

नाइजर

बंदरगाह विहीन पश्चिमी अफ्रीकी अर्थव्यवस्था नाइजर काफी हद तक कृषि और यूरेनियम खनन पर निर्भर है। जुलाई 2023 में सैन्य तख्तापलट के कारण पूर्व राष्ट्रपति को अपदस्थ करने और पश्चिम अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय (इकोवास) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण नाइजर की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2022 की 11.9% से गिरकर 2023 में 1.4% रही। फरवरी 2024 में ECOWAS द्वारा प्रतिबंधों को हटाने से 2024 में आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने की उम्मीद है। मुख्य रूप से मई 2024 से नाइजर–बेनिन पाइपलाइन से तेल उत्पादन और निर्यात में बड़े पैमाने पर वृद्धि के कारण वास्तविक जीडीपी 2024 में 10.4% रहने का अनुमान है। वर्ष 2023 में औसत वार्षिक मुद्रास्फीति घटकर 3.7% हो गई, लेकिन कम कृषि उत्पादन और सीमा बंद होने के कारण अगस्त से बढ़ी है तथा 2024 में उच्च मुद्रास्फीति के दबाव की संभावना है। नाइजर–बेनिन पाइपलाइन से तेल निर्यात शुरू होने से 2024 में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.1% तक कम होने की उम्मीद है, जिससे निर्यात में बड़ी वृद्धि होगी। यूरो के मुकाबले लिए सीएफए फ्रैंक के 2024 में मजबूत होने की उम्मीद है। 2023 में 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 606.1 के स्तर पर रही सीएफए फ्रैंक के 2024 में 596.3 के स्तर पर रहने की उम्मीद है। ■

मुद्रा की प्रवृत्तियां

सौजन्य : **ट्रेजरी एंड अकाउंट्स ग्रुप**

मैक्सिकन पेसो

Ps 1979 में तेल संकट के बाद, मेक्सिको ने कई वर्षों तक मुद्रास्फीति और ऋण चूकों का सामना करना पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप 1993 में इसने अपनी मुद्रा को `न्यूवो' को बदलकर मेक्सिकन पेसो (एमएक्सएन) कर दिया। अब यही मेक्सिको की आधिकारिक मुद्रा है। पेसो की ताकत इसकी निम्न अस्थिरता और मेक्सिको की रिकॉर्ड–उच्च ब्याज दरें रही हैं, जो वर्तमान में 11% हैं, जो किसी मुद्रा में उधार लेने और पेसो में ऋण देने को आकर्षक बनाती हैं।

मेक्सिको में सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी के एएमएलओ को हराकर मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के चुनाव ने उन निवेशकों को आश्चर्यचकित करने का काम किया, जो प्रस्तावित सुधारों के बारे में चिंतित थे। उनकी चिंता अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने और सत्तारूढ़ पार्टी का शासन से नियंत्रण खत्म होने को लेकर थी। इन प्रस्तावित अठारह प्रस्तावों में सर्वोच्च न्यायालय में सुधार, चुनाव सुधार और उदार शासन के लिए मेक्सिको के पारदर्शी निकाय INAI को भंग करना शामिल है। मेक्सिको की मुद्रा 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 18.36 पर बंद हुई, जो चुनाव परिणाम से एक सप्ताह पहले की तुलना में लगभग 10% कम रही। बाजार मेक्सिको के मौजूदा बजट घाटे को लेकर भी चिंतित है, जो जीडीपी के 6% के बराबर है। उच्च घरेलू ब्याज दरों के बावजूद मेक्सिको लगातार उच्च मुद्रास्फीति से जूझ रहा है। मॉर्गन स्टेनली ने चेतावनी दी है कि एक अपरंपरागत सरकार मेक्सिकन संस्थाओं और मैक्सिकन पेसो को कमजोर कर सकती है, जिससे पेसो और भी कमजोर हो सकता है।

20 जून, 2024 को एमएक्सएन एक डॉलर के मुकाबले 18.3716 पर बंद हुआ।

जापानी येन

¥ जापानी येन एशिया में सबसे अधिक और दुनिया में तीसरी सबसे अधिक ट्रेड की जाने वाली मुद्रा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई और एक यूएस डॉलर के मुकाबले येन की विनिमय दर 360 येन पर तय की गई। तथापि, यह व्यवस्था 1971 के बाद समाप्त कर दी गई। मई 2024 में जापान में केंद्रीय बैंक की पॉलिसी दर 0.05 प्रतिशत रही। मार्च 2024 में, बैंक ऑफ जापान ने अपनी ऋणात्मक ब्याज दर नीति को समाप्त करते हुए 17 वर्षों में पहली बार अल्पकालिक ब्याज दरें बढ़ाईं।

2022 से जापानी येन के मूल्य में गिरावट मुख्य रूप से बढ़ते व्यापार घाटे के साथ–साथ घरेलू और विदेशी ब्याज दरों के बीच के अंतर के कारण रही है। जापानी वित्त मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा बाजार में जापानी येन में मजबूती लाने के लिए 26 अप्रैल से 29 मई के बीच रिकॉर्ड 9.8 ट्रिलियन जापानी येन (62.2 बिलियन यूएस डॉलर) खर्च किए। यह हस्तक्षेप अप्रैल में यूएसडी/जेपीवाई विनिमय दर के 160.21 के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद आया, जिससे बैंक ऑफ जापान को हस्तक्षेप करना पड़ा और 3 मई को एक यूएस डॉलर के मुकाबले जापानी येन की कीमत 151.92 रही।

सुदृढ़ यूएस सीपीआई प्रिंट के बाद, फेड कटौतियों की उम्मीदें और कम हो गई हैं और बाजार अब 2024 में कीमतों में केवल 50 बीपी की कटौती के आसपास है। इस प्रकार, यूएसडी के मुकाबले जापानी येन की कीमत जून, सितंबर, दिसंबर 2024 में क्रमशः 155, 154, 153 और मार्च 2025 में 153 रहने का पूर्वानुमान है।

20 जून, 2024 को एक डॉलर के मुकाबले जापानी येन 158.9320 पर बंद हुआ।

केन्याई शिलिंग

Ksh 1966 में शुरू की गई केन्याई शिलिंग (केईएस), पूर्वी अफ्रीका की एक स्थिर मुद्रा है, जो पिछले दशक में यूएस डॉलर की तुलना में कमजोर हो गई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में केन्या की जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर 5.8% तक पहुंच गई, जिससे यह उप–सहारा अफ्रीका में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है।

केंद्रीय बैंक का मत था कि संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए शिलिंग का मूल्यह्रास आवश्यकता से अधिक हो गया था। इस कारण केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 5 दिसंबर, 2023 को पॉलिसी ब्याज दर को 10.5% से बढ़ाकर 13% कर दिया।

तथापि, बाजार की उम्मीदें इस उपाय से भी नहीं बदलीं। शिलिंग में गिरावट जारी रही और 25 फरवरी, 2024 तक शिलिंग का मूल्य एक यूएस डॉलर के मुकाबले घटकर 163 तक पहुंच गया। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ, क्योंकि शिलिंग को कमजोर रखने के पीछे केन्या के परिपक्व हो रहे यूरोबॉन्ड ऋण पर संभावित चूक को लेकर निवेशकों के डर जैसे और भी कारण थे।

बाजार संचालित मुद्रा शिलिंग फ्री–फ्लोटिंग मुद्रा नहीं है। इसमें उतार–चढ़ाव को कम करने या आगे आने वाले उतार–चढ़ाव को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा प्रायः हस्तक्षेप किया जाता है। बाजार में भावनाएं काम करती हैं और ये भावनाएं मुद्रा के मूल्यों को प्रभावित कर सकती हैं। यह तब भी देखा गया जब केन्या ने अपने यूरोबॉन्ड ऋण का कुछ हिस्सा चुका दिया और शिलिंग के संप्रभु चूक के संभावित जोखिम को कम कर दिया।

तथापि, ये परिवर्तन स्थिर नहीं हैं, क्योंकि मुद्रा के अवमूल्यन को रोकने के लिए उपयोग किया जाने वाला विदेशी मुद्रा भंडार असीमित नहीं है। इसलिए, शिलिंग को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सुदृढ़ आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों की आवश्यकता होती है।

20 जून, 2024 को शिलिंग एक यूएस डॉलर के मुकाबले 128.21 पर बंद हुआ।

ब्राज़ीलियाई रियाल

R वर्तमान मुद्रा, ब्राज़ीलियाई रियाल (बीआरएल) ने दो दशकों के उच्च मुद्रास्फीति और अति मुद्रास्फीति चक्र के बाद, जुलाई 1994 में क्रूज़ेरो रियाल की जगह ले ली। केंद्रीय बैंक, बैंको सेंट्रल डो ब्रासील (बीसीबी), रिकवरी में सहयोग करने के लिए ब्याज दरों में कमी करता रहा है, जो वर्तमान में 10.50% हैं। श्रम बाजार तंग बना हुआ है, जिससे वेतन में सुदृढ़ वृद्धि और उपभोक्ता व्यय में वृद्धि हो रही है। तथापि, बीसीबी द्वारा हाल ही में ब्याज दरों में कटौती के कारण बीआरएल कमजोर हो गई है और यूएस डॉलर के मुकाबले इसका मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतर बना हुआ है।

ब्राज़ील में राजकोषीय असंतुलन की चिंताओं और राष्ट्रपति लूला के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि जारी रखने के वादे के कारण जून में बीआरएल कमजोर होकर 18 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। एक यूएस डॉलर के मुकाबले यह 5.4 बीआरएल के स्तर पर आ गया। इस बीच, निवेशकों ने मई की मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बाद मुद्रास्फीति के 3.76% से घटकर 3.96% रहने की उम्मीद जताई है।

20 जून, 2024 को बीआरएल एक डॉलर के मुकाबले 5.4496 पर बंद हुआ। ■

आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था

सौजन्य: **शोध एवं विश्लेषण समूह**

भारत का मर्चेंडाइज़ व्यापार

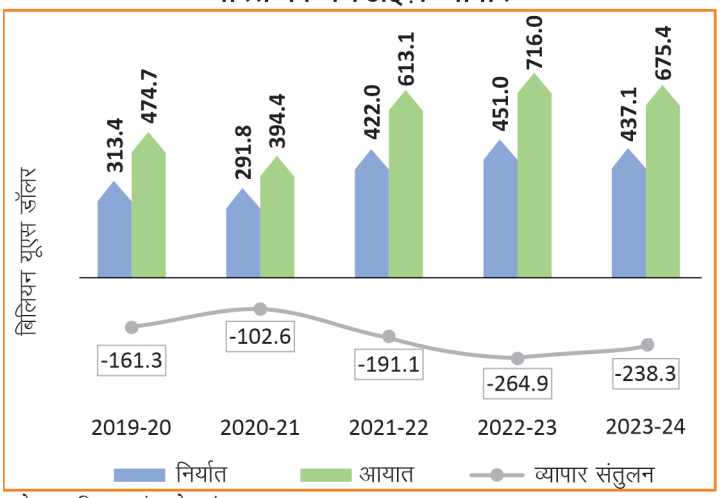

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

भारत की सेवाएं व्यापार

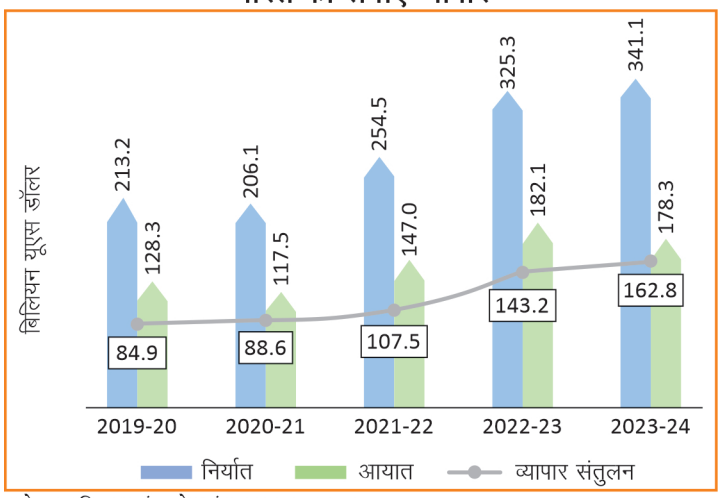

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

चालू खाता घाटा

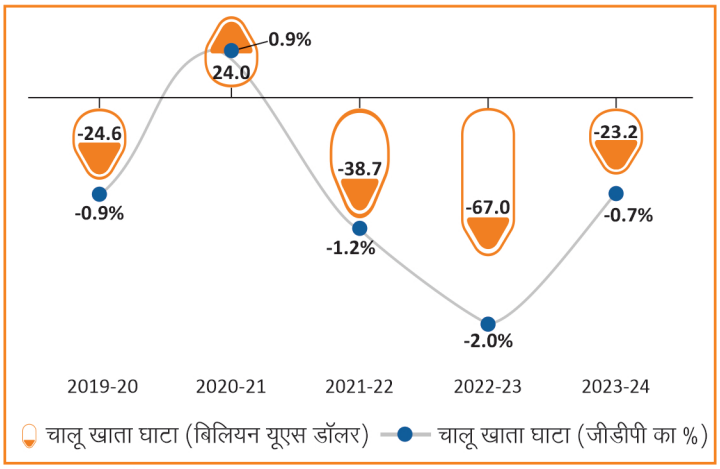

स्रोत: आरबीआई

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)

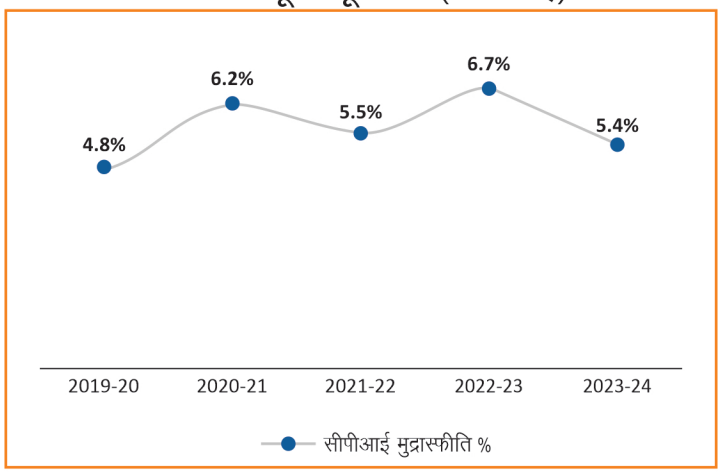

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह

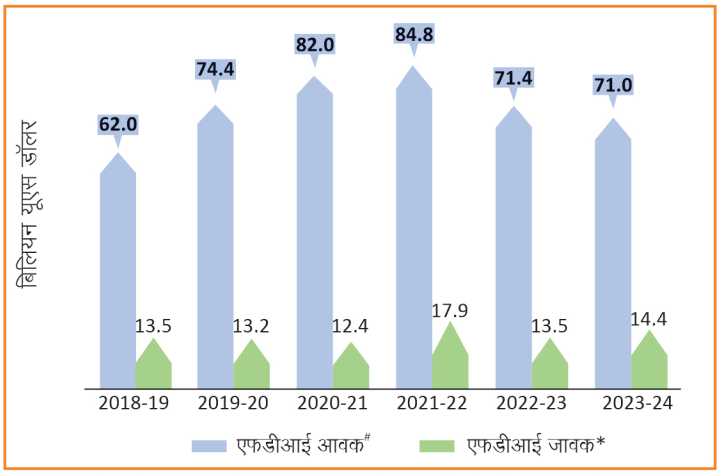

*नोट: *एफडीआई जावक वास्तविक आंकड़े दर्शाते हैं और इसमें इक्विटी, ऋण, इन्वोक की गारंटियां शामिल हैं।*
#एफडीआई आवक में इक्विटी, पुनर्निवेश आय और अन्य पूंजी शामिल है।
स्रोत: आरबीआई और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

भारत की आर्थिक वृद्धि

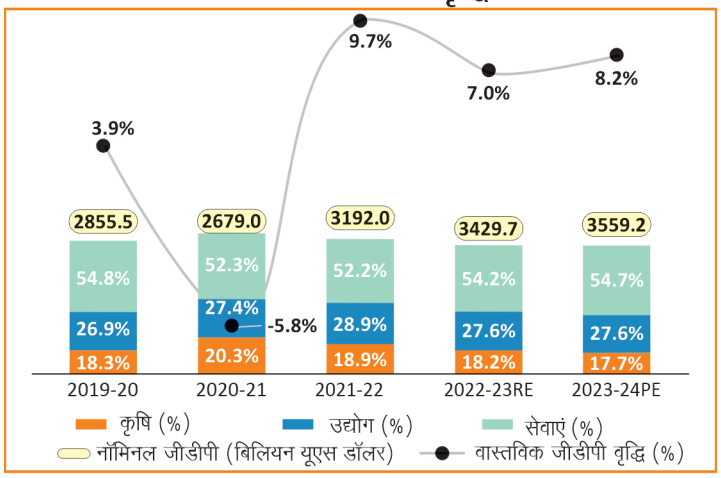

नोट: पीले रंग के आंकड़े नॉमिनल जीडीपी (बिलियन यूएस डॉलर) को दर्शाते है ;
आरई– संशोधित अनुमान ; पीई– अंतिम अनुमान
स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान फाइनेंस एंड सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार